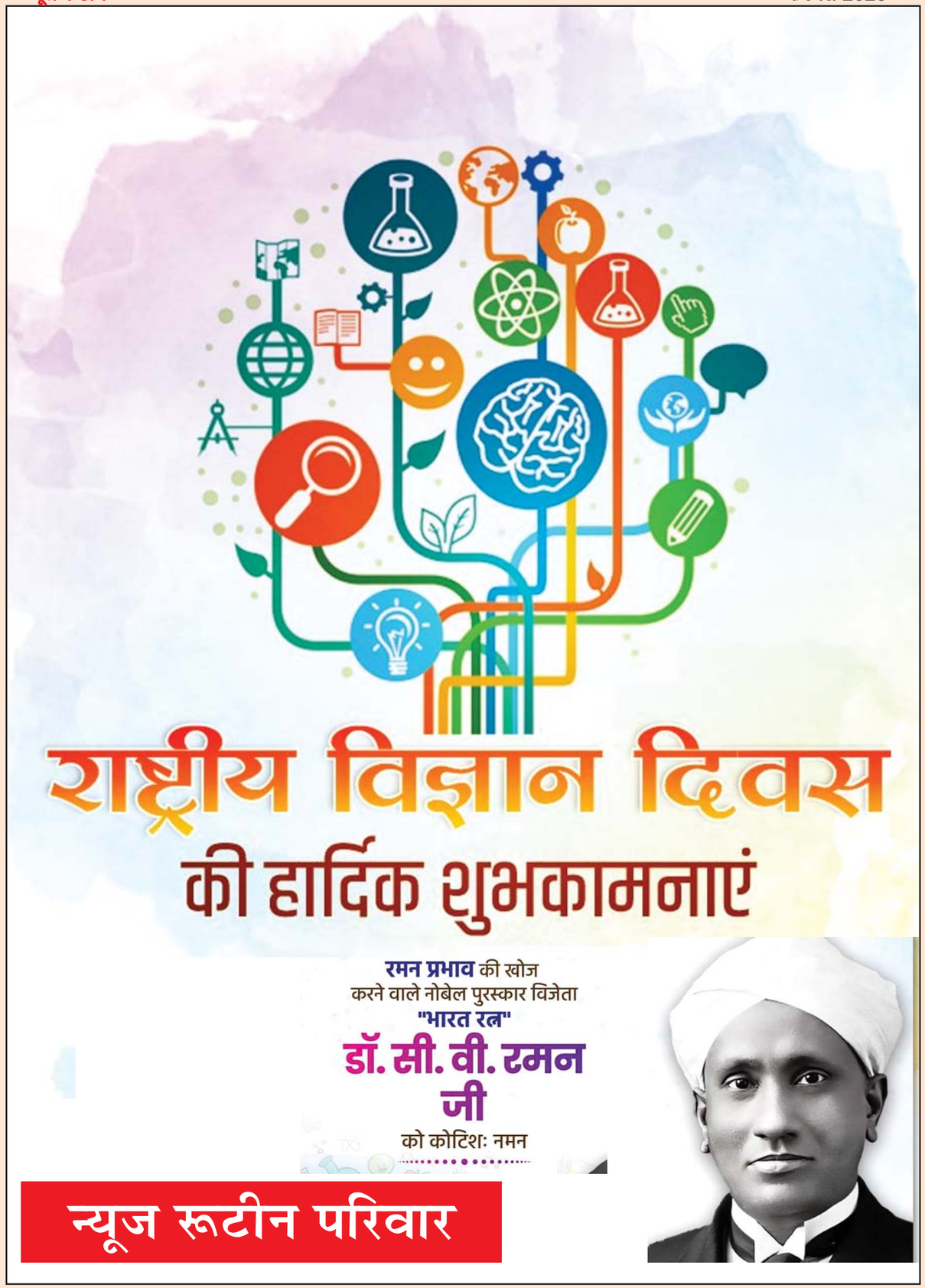

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

रमन प्रभाव की खोज
करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता
"भारत रत्न"
डॉ. सी. वी. रमन जी
को कोटिशः नमन

न्यूज रूटीन परिवार

RNI NO. CHHHIN/2022/83778
E-mail: newsroutine6@gmail.com

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम
वर्ष- 05 अंक -02 फरवरी 2026 मूल्य - 35 रु.

संविधान और सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण

Follow Us :- @newsroutine @newsroutine @newsroutine @newsroutine

150 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 100 एकड़ में विकसित होगी फिल्म सिटी

मुख्यमंत्री साय ने चित्रोत्पला फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर का किया भूमि पूजन

छत्तीसगढ़ का बरसों पुराना सपना आज साकार हो गया है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा, बल्कि यह परियोजना राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा, निवेश के नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में राज्य के युवाओं, कलाकारों और पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के ग्राम माना-तूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों, फिल्म कलाकारों, निर्माता-निर्देशकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के अभिनय और कला जगत से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी के माध्यम से प्रदेश के हजारों हुनरमंद कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। स्थानीय फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी तकनीकी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के लिए केंद्र सरकार से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश की कला और कलाकारों को उचित सम्मान मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने भूमिपूजन के साथ ही फिल्म निर्माण और कन्वेंशन सेंटर से संबंधित विभाग को चार प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में फिल्म निर्माण गतिविधियों को नई गति मिलेगी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक एवं सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों को बड़े पर्दे पर स्थान मिलेगा।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज का यह अवसर छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं फिल्म विकास उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल एक निर्माण परियोजना की शुरुआत नहीं है, बल्कि राज्य के सांस्कृतिक, आर्थिक और रचनात्मक भविष्य की सशक्त नींव है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण राज्य है और इस पहल से पर्यटन के साथ-साथ फिल्म उद्योग को भी नया आयाम मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माताओं के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। हमारी स्पष्ट योजना है कि आगामी दो वर्षों के भीतर इन परियोजनाओं को पूर्ण कर राज्य को समर्पित किया जाएगा।

इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुश्री मोना सेन, छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल तथा पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी के प्रस्तावित मास्टर प्लान का किया अवलोकन

चित्रोत्पला फिल्म सिटी एवं ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के भूमिपूजन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने परियोजना के प्रस्तावित मास्टर प्लान का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं तथा परियोजना पर आधारित एक लघु फिल्म भी देखी।

चित्रोत्पला फिल्म सिटी के भूमिपूजन अवसर पर पर्यटन विभाग को मिले 4 प्रस्ताव

चित्रोत्पला फिल्म सिटी के भूमिपूजन के साथ ही पर्यटन विभाग को फिल्म निर्माण एवं कन्वेंशन सेंटर में इकाइयों की स्थापना हेतु चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। समारोह के दौरान ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे गए।

उपनिषद से एआई तक विषय पर परिचर्चा

भाषा के मानकीकरण में एआई की भूमिका बड़ी चुनौती

नवा रायपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव 2026 के दूसरे दिन कवि-कथाकार अनिरुद्ध नीरव मंडप पर साहित्य - उपनिषद से एआई तक विषय पर केंद्रित परिचर्चा आयोजित हुई। इस परिचर्चा में वक्ता के रूप में ट्रिपल आईटी नवा रायपुर के डायरेक्टर डॉ. ओमप्रकाश व्यास, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ लेखक डॉ. गोपाल कमल शामिल हुए। परिचर्चा के सूत्रधार साहित्यकार श्री संजीव तिवारी रहे, परिचर्चा का यह सत्र कवि जगन्नाथ प्रसाद भानु को समर्पित रहा। इस अवसर पर डॉ. गोपाल कमल द्वारा लिखित पुस्तक, गुणाढ्य की गुणसूत्र कथा का विमोचन किया गया।

ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर डॉ. ओमप्रकाश व्यास ने कहा कि एआई का जो रूप आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे विगत 30ङ्क40 वर्षों की मेहनत है। एआई निरंतर निखरता जा रहा है। तकनीक खुद को परिमार्जित करती जाती है, यह प्रक्रिया सतत है। एआई नेट पर उपलब्ध जानकारी, आंकड़ों और सूचनाओं का विश्लेषण कर हमें डिस्क्रिप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में समझाता है। धीरे-धीरे एआई निखरा और प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में काम करने लगा। आज एआई भविष्य की चीजों को भी बताता है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2022 में पहली बार चैट जीपीटी आया। सिर्फ तीन साल में एआई का रूप कितना भव्य हुआ है, आप देखिए। हम एआई के भविष्य की अब कल्पना भी नहीं कर सकते। भाषा के मानकीकरण में एआई की क्या भूमिका होगी, यह हम सभी के बीच एक बड़ी चुनौती है।

प्रश्न जितना गहरा, उत्तर भी उतना ही गहरा होगा- प्रफुल्ल केतकर

वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रफुल्ल केतकर ने परिचर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि गीता के 18 अध्यायों में सभी तरह के ज्ञान का समावेश है। एआई को लेकर लोग चिंतित हैं कि एआई का फ्यूचर क्या होगा। एआई के आधार पर जापान ने जब रोबोट बनाया तो वह स्वयं को नेगेटिव प्रॉम्प्ट देने लगा। एआई कमांड और प्रॉम्प्ट पर काम करता है। एआई वही बताता है जो नेट पर उपलब्ध है। श्री केतकर ने कहा कि हमारे ऋषि सूचना की नहीं, ज्ञान की बात करते थे। वे एआई से बहुत ज्यादा आगे थे। यदि हम मैकाले की शिक्षा पद्धति की बात करें तो उसने हमें अच्छा उत्तर लिखने वाला बना दिया। प्रश्न जितना गहरा होगा, उत्तर भी उतना ही गहरा होगा। मानव के ज्ञान का उद्देश्य प्रकृति पर विजय पाना नहीं, उसके नियमों को समझकर अपने आपको प्रकृति के अनुरूप ढालना था।

हमारे साथ में सोचने की परंपरा ऋग्वेद से आती है-डॉ. गोपाल कमल

वरिष्ठ लेखक डॉ. गोपाल कमल ने सत्र में अपने संबोधन में कहा कि हमारे साथ में सोचने की परंपरा ऋग्वेद से आती है। हम सभी एआई में डीप लर्निंग की बात करते हैं। भाषा कहां से आती है, वह आकार कैसे लेती है, मनुष्य भाषा तक कैसे पहुंचा, इस पर होने वाले कार्य और अध्ययन को साइकोलिंग्विस्टिक के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक कोड के जरिए ही हम नई चीजों को सीख पाते हैं। डॉ. गोपाल ने कहा कि सोमदेव ने कथासरितसागर के नाम से संस्कृत में पुस्तक लिखी, इसे हम गुणाढ्य के रूप में देख सकते हैं। संस्कृत के लगभग 3900 सूत्र हैं। महेश्वर सूत्रों से हम सभी शब्दरूप और धातुरूप बना सकते हैं। एआई में हम जीरो से एक का सहारा लेते हैं। गुणसूत्र की भाषा से एआई के संचार नेटवर्क को गढ़ा गया है।

हमारा उपनिषद एआई का मूल-संजीव तिवारी

परिचर्चा के सूत्रधार, साहित्यकार श्री संजीव तिवारी ने कहा कि मेरे समझ में उपनिषद और एआई एक जैसे हैं। वेद ज्ञान का खजाना है, जिसका भाष्य उपनिषद है। एआई भी प्रश्नोत्तर शैली में उत्तर देता है। हमारा उपनिषद एआई का मूल है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे संस्थान एआई को लेकर काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए दूसरे संस्थान भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि एआई में बेहतर से बेहतर रूप में छत्तीसगढ़ी भाषा निखरकर आ सके। इस अवसर पर गणमान्य साहित्यकार एवं श्रोता उपस्थित रहे।

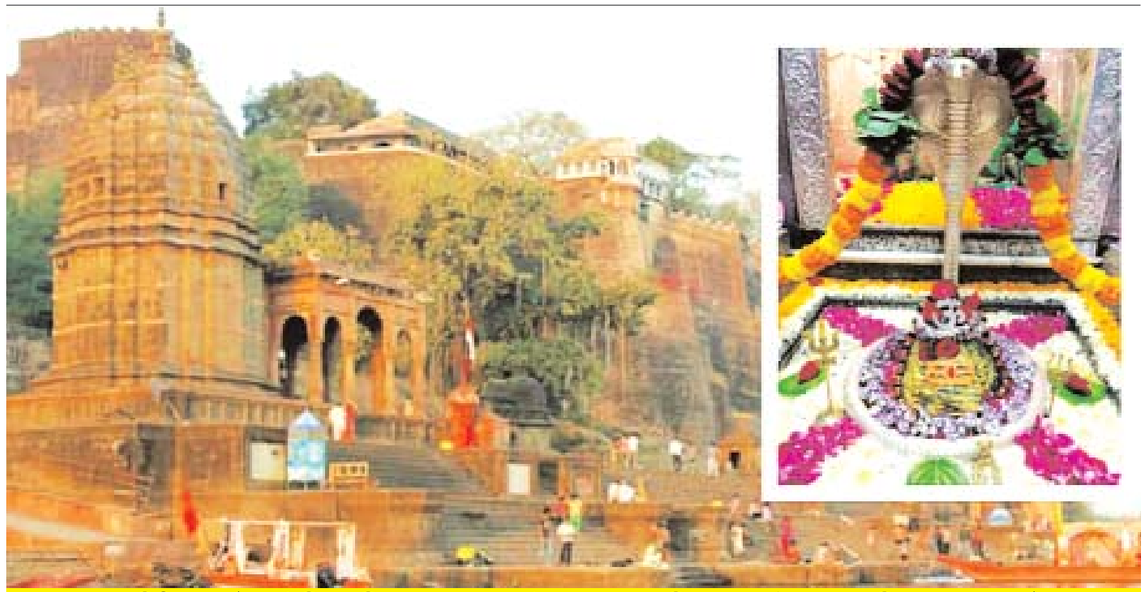

धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण शिवभक्तों का पवित्र स्थल है

ओंकारेश्वर

ओंकारेश्वर मंदिर, भगवान शिव के एक प्रमुख रूप ओंकारेश्वर के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले भक्त विशेष रूप से ओंकारेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसे नर्मदा नदी के दर्शन के साथ पूजा जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य के खरगोन जिले में स्थित ओंकारेश्वर एक प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थल है। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। ओंकारेश्वर भगवान शिव के एक प्रसिद्ध रूप, ओंकारेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है और यह स्थल देश भर से भक्तों को आकर्षित करता है। यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण ओंकारेश्वर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है।

ओंकारेश्वर का इतिहास

ओंकारेश्वर का नाम 'ओंकार' (ऊँ कार) और 'ईश्वर' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'ऊँ' (ब्रह्मांड का प्रतीक) के रूप में भगवान शिव। इस स्थल का इतिहास बहुत पुराना है और यह महाभारत और पुराणों में भी वर्णित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां पर अपनी पूजा के लिए एक दिव्य रूप में अवतार लिया था। ओंकारेश्वर का मंदिर प्राचीन काल से ही हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है।

ओंकारेश्वर के प्रमुख आकर्षण

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर- ओंकारेश्वर मंदिर, भगवान शिव के एक प्रमुख रूप ओंकारेश्वर के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग को समर्पित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ आने वाले भक्त विशेष रूप से ओंकारेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं, जिसे नर्मदा नदी के दर्शन के साथ पूजा जाता है। मंदिर का वास्तुशिल्प बहुत भव्य है और यहाँ का वातावरण अत्यधिक शांति और श्रद्धा से भरा हुआ होता है।

महाकालेश्वर मंदिर- ओंकारेश्वर मंदिर के समीप एक अन्य प्रसिद्ध स्थल महाकालेश्वर मंदिर है। यह भी भगवान शिव को समर्पित है और यहां पर विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर को भी ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है। यह मंदिर शांति और ध्यान के लिए एक आदर्श स्थल है।

नर्मदा नदी और घाट- ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के घाटों पर पूजा अर्चना करना एक विशेष अनुभव होता है। भक्तों के लिए नर्मदा नदी में स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त का दृश्य देखना भी बहुत मनमोहक होता है।

ओंकार पर्वत- ओंकारेश्वर मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में ओंकार पर्वत भी शामिल है, जो मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर स्थित एक शिला पर भगवान शिव के स्वरूप का चित्रण किया गया है। ओंकार पर्वत की चोटी से पूरे ओंकारेश्वर का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है।

कांच मंदिर और अन्य छोटे मंदिर- ओंकारेश्वर में कई छोटे-छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें कांच मंदिर प्रमुख है। इन मंदिरों का वास्तुशिल्प और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्तों को आकर्षित करते हैं।

ओंकारेश्वर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसे ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिन्दू धर्म के अनुसार, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में स्थित हैं, जिनमें से ओंकारेश्वर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां की यात्रा से भक्तों को मानसिक शांति, मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। ओंकारेश्वर का स्थान शिवजी के प्रमुख मंदिरों में गिना जाता है और हर वर्ष यहां लाखों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं।

ओंकारेश्वर का मौसम

ओंकारेश्वर का मौसम पूरे साल अच्छा रहता है।

गर्मियाँ (मार्च से जून)-गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी नर्मदा नदी का ठंडा पानी और घाटों पर शांति बनाए रखते हैं।

मानसून (जुलाई से सितंबर)- मानसून के मौसम में नर्मदा नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है और वातावरण में ताजगी होती है।

सर्दियाँ (नवंबर से फरवरी)- सर्दियों में यहां का मौसम बहुत ही सुखद और ठंडा होता है, जो यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है।

ओंकारेश्वर कैसे पहुंचें

वायु मार्ग- ओंकारेश्वर का नजदीकी हवाई अड्डा इंदौर में स्थित है, जो लगभग 77 किलोमीटर दूर है। इंदौर से ओंकारेश्वर के लिए टैक्सी और बस सेवाएं उपलब्ध हैं।

रेल मार्ग- ओंकारेश्वर का नजदीकी रेलवे स्टेशन ओंकारेश्वर रोड है, जो यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्टेशन से ओंकारेश्वर पहुंचने के लिए टैक्सी और ऑटो रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है।

न्यूज रूटीन

बढ़ते हुए कदम

● वर्ष: 05 ● अंक:02 ● फरवरी 2026

RNI NO. CHHHIN/2022/83778

E-mail: newsroutine6@gmail.com

सारंगढ़-बिलाईगढ़

प्रधान संपादक

गुलाब दास दीवान

सहसंपादक

प्रवीण खरे

कानूनी सलाहकार

जवाहर पड़वार

इंदुभूषण पड़वार

प्रधान कार्यालय

न्यूज रूटीन

बाजार काम्पलेक्स, नगर पंचायत पवनी,
जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़
पिन. नं. 493338
मो.नं. 9294743139

रायपुर कार्यालय

फ्लैट नं. 109, सी ब्लाक, कमल हाईट्स,
सेक्टर-4, कमल विहार, रायपुर (छ.ग.)
पिन नं. 492004
मो. नं. 6261155546

न्यूज रूटीन में प्रकाशित आलेखों से संपादक, प्रकाशक, मुद्रक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। विवादग्रस्त न्यायिक प्रकरणों का कार्यक्षेत्र सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला रहेगा। सभी पद पूर्णतः मानसेवी व अवैतनिक। समाचार स्त्रोत हमारे सभी संवाददाता/प्रतिनिधि। संदर्भ सामग्रीः इंटरनेट, प्रमुख समाचार पत्र एवं नामचीन पत्रिकाओं से सादर साभार।

संपादक- गुलाब दास दीवान

अंदर के पृष्ठों में

7 आधुनिक घोटुल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा

14 नक्सलगढ़ में गूंजा राष्ट्रगान

- छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना को लेकर बजट में मिल... 6
- संविधान, लोकतंत्र और सुशासन के रास्ते विकसित 8
- अंतरिक्ष केंद्र बनेगी युवा सपनों को पूरा करने की प्रयोगशाला 10
- प्रदूषण फैलाते छत्तीसगढ़ के मेडिकल हब 13
- पर्यटन बना छत्तीसगढ़ का आर्थिक इंजन, संस्कृति बनी पहचान 18
- अजित पवार-आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा' 20
- राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 23
- सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी की दरकार 26
- मीडिया के नए रूप में भी प्रगति के भरपूर अवसर 29
- ...शिवभक्तों का पवित्र स्थल है -ओंकारेश्वर 30

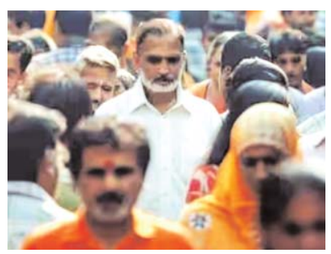

2050 तक भारत में 34 करोड़ होंगे बुजुर्ग

28

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- गुलाब दास दीवान, द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. (छ.ग.) भवन, प्रेस काम्पलेक्स रजबंधा मैदान रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं ग्राम-पोस्ट-पवनी, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.), 493338 से प्रकाशित। RNI NO. CHHHIN/2022/83778 सम्पादक- गुलाब दास दीवान, मो. 9294743139

खास तरह का आम बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक अनिश्चितता के बीच गैर-लोकलुभावन बजट पेश किया। यह अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्थिरता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें सीधे लाभ की बजाय बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास पर जोर है। मुख्य तत्व आर्थिक अनुशासन और राजकोषीय घाटे को कम करना है, जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत करना है। एमएसएमई और उद्योग जगत को बदलाव का संदेश दिया गया है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब आम बजट को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे थे, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लीक से हटकर चलने का फैसला किया। यह समय की मांग भी थी। इसी कारण इस बजट में कोई चौंकाने वाली या फिर लोकलुभावन घोषणा नहीं। ऐसा इसीलिए है, क्योंकि अनिश्चित माहौल में कोई योजना बनाना एक तरह से अंधेरे में तीर मारना होता।

मोदी सरकार ने बजट के जरिये अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसे स्थिरता प्रदान करने वाले फैसले लिए हैं। यह भी दिख रहा है कि उसकी कोशिश आर्थिक मोर्चे पर स्थितियों को सुधारने पर जोर देना है। इसी कारण यदि आम या खास आदमी इस बजट में सीधे तौर पर खुद को लाभान्वित होता हुआ नहीं देख रहा है तो आश्चर्य नहीं। इसका यह अर्थ भी नहीं कि उसे परोक्ष तौर पर भी कुछ मिलने नहीं जा रहा है। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सामाजिक विकास की अनेक योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों को राहत या सुविधाएं देने की कोशिश की गई है।

निःसंदेह बजट पर शेयर बाजार ने निराशाजनक प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह पहली बार नहीं, जब शेयर बाजार को बजट रास नहीं आया हो। चूंकि यह बजट पारंपरिक नहीं है, इसलिए उसकी व्याख्या भी नए तरीके से की जानी चाहिए। बजट का केंद्रीय तत्व आर्थिक और वित्तीय अनुशासन है, इसका एक प्रमाण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को और कम करना है। इसके अतिरिक्त उन योजनाओं पर पैसा खर्च करना भी है, जिनसे देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत हो और आत्मनिर्भर भारत की नींव सशक्त बने।

बजट में ऐसे कई उपाय किए गए हैं, जो उद्योग-व्यापार जगत को सीधा संदेश देते हैं कि उसे अपने तौर-तरीके बदलने होंगे। यदि भारतीय उद्योग जगत को चुनौतियों से पार पाना है तो उसे यह करना ही होगा। यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौते के बाद ऐसा करना और भी आवश्यक हो गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जाए कि हमारा उद्योग जगत वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार नहीं। कहना कठिन है कि इस बजट की घोषणाएं उसे इसके लिए प्रेरित कर सकेंगी या नहीं?

जो भी हो, यह अच्छा है कि सरकार ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम यही बता रहे हैं कि जो काम छोटे और मझोले कारोबारियों को करना चाहिए, उसमें सरकार हाथ बंटाने के लिए आगे आ रही है। यदि इसके बाद भी एमएसएमई क्षेत्र सक्षम नहीं बनता तो यह निराशाजनक ही होगा। वास्तव में छोटे-बड़े, सभी कारोबारियों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझनी होगी।

इसी तरह नौकरशाही को भी अपने रंग-ढंग बदलने होंगे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास और ऐसी ही अन्य बड़ी योजनाओं का वही हश्र होगा, जो स्मार्ट सिटी योजना का हुआ। यह समझना होगा कि शहरों का विकास करने की जिम्मेदारी मूलतः राज्यों और नगर निकायों की है। केंद्र सरकार ऐसे कुछ नियम-कानून अवश्य बना सकती है, जिनसे राज्य सरकारें और नगरीय विकास की एजेंसियां अपना काम कुछ उसी तरह करें, जैसे मेट्रो परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के मामले में किया जा रहा है। बजट में सीधे तौर पर टैक्स छूट देने के बजाय टैक्स संबंधी नियम-कानूनों का सरलीकरण करने और कठोर दंडात्मक उपायों से परे जाने के जो अनेक फैसले किए गए हैं, उनसे लोगों को सचमुच राहत भी तभी मिलेगी, जब नौकरशाही का रवैया बदलेगा।

जो भी हो, यह अच्छा है कि सरकार ने बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम यही बता रहे हैं कि जो काम छोटे और मझोले कारोबारियों को करना चाहिए.....

संपादक

मीडिया के नए रूप में भी प्रगति के भरपूर अवसर

अशोक जोशी

वह जमाने लद गए जब मीडिया को केवल समाचार पत्र पत्रिकाओं या सैटेलाइट आधारित पत्रकारिता के लिए जाना जाता था। आज मीडिया का स्वरूप बदल गया है। जब से डाटा और एआई मीडिया पर हावी हुए हैं, मीडिया में कैरियर निर्माण के ट्रेंड भी बदल गए हैं। जो युवा मीडिया में नए कैरियर की तलाश में हैं उनके लिए कैरियर निर्माण की नई राहें खुली हैं। मीडिया के काम करने का तरीका वैज्ञानिक रूप ले चुका है। मीडिया जगत में सामग्री संकलन से लेकर डाटा कलेक्शन, स्टोरीलाइनिंग से लेकर प्रेजेंटेशन सभी में डिजिटल हस्तक्षेप आरम्भ हो चुका है। आज मीडिया के छात्र, उभरते पत्रकार और प्रोफेशनल्स सभी अपने कैरियर को नई धार देने के लिए प्रयत्नशील हैं।

एआई को अपनाएं, नई राह पाएं

आजकल मीडिया प्रेजेंटेशन क्रिएटिव रूप ले चुका है। दर्शकों की रुचि जगाने के लिए डिजाइनिंग और एनिमेशन का प्रयोग बढ़ा है। एआई की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो सिक्वेंस बनाए जा रहे हैं। अब केवल यह मीडिया क्षेत्र केवल रिपोर्टिंग करने वालों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि आईटी प्रोफेशनल्स भी मीडिया से जुड़ रहे हैं। एआई से जो डिजाइन और एनिमेशन तैयार होते हैं, वह टीवी चैनलों, अखबारों तथा पत्रिकाओं की स्टोरीटेलिंग कैपिसिटी और क्रिएटिविटी को पंख लगाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज के साथ ग्राफिक्स और एनिमेशन का प्रयोग बढ़ रहा है।

बढ़ता डाटा जर्नलिज्म का दायरा

आजकल टीवी चैनल या अखबारों में प्रमुख खबरों के साथ डाटा का बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है जिससे उस अखबार या चैनल की स्टोरी या आंकड़ों के विश्लेषण को प्रभावी बनाया जा सके। इसके लिए मीडिया हाउसों में डाटा जर्नलिस्ट की भर्ती की जाने लगी हैं। यह डाटा जर्नलिस्ट परम्परागत पत्रकार या खबर खोजी नहीं होते। उनमें डाटा एनालिसिस , स्टेटिस्टिक्स और कोडिंग की खास प्रतिभा होती है। इन्हें शानदार पे पैकेज भी ऑफर किए जा रहे हैं।

सोशल मीडिया ने बढ़ाए अवसर

मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया को भी आज जनसाधारण के विचारों को प्रभावित करने के लिए उपयोग में लाया जाने लगा है। इसके लिए व्यापारिक संस्थानों से लेकर फिल्म जगत और सामाजिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी क्षेत्रों में सोशल मीडिया एक्सपर्ट की मांग बढ़ी है जो उचित समय पर ऐसा प्रभावशाली कंटेंट तैयार करें जो टारगेट आडियंस को प्रभावित कर सके। उत्पादों के विक्रय से लेकर राजनीतिक मैदान में सोशल मीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। इन दिनों सोशल मीडिया आधुनिक पत्रकारिता का आधार स्तंभ बन गया है। कंटेंट तैयार करने में इसका बहुत योगदान देखने में आया है। सोशल मीडिया मैनेजर्स और कंटेंट रणनीतिकार को हायर किया जाने लगा है। वहीं मीडिया इंडस्ट्री से लेकर बिजनेस के लगभग सभी क्षेत्रों में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स की मांग बेतहाशा बढ़ी है।

तकनीकी प्रगति का असर मीडिया पर भी पड़ा है। प्लेटफॉर्म के तौर पर अखबार व टीवी के साथ ही सोशल मीडिया के विभिन्न मंच एक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक व इंस्टा आदि जुड़े हैं। मल्टी मीडिया का उपयोग बढ़ा है जिसे अब एआई ने पंख लगा दिये। ऐसे में पत्रकारों के अलावा ज्यादा पेशेवरों और विभिन्न क्षेत्रों के माहिरों के लिय भी मीडिया में कैरियर के अवसर बढ़े हैं

कंटेंट रहेगा सदाबहार

मीडिया में कैरियर बनाने वाले ध्यान रखें कि कंटेंट ही मीडिया प्रेजेंटेशन पर राज करता है। जिसका कंटेंट जितना प्रभावशाली और विश्वसनीय होगा आम जनता में उसका उतना ही प्रभाव होगा। इसीलिए आजकल प्रिंट मीडिया से लेकर सैटेलाइट मीडिया और यहां तक मनोरंजन के क्षेत्र में भी कंटेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाने लगा है। आजकल कंटेंट प्रेजेंट करने वाले स्पेशलिस्ट भी तैयार होने लगे हैं जो दर्शकों या टारगेट ग्रुप की पसंद को ध्यान में रखकर कंटेंट तैयार करते हैं और उसे रोचक तरीके से पेश कर अपना टीआरपी बढ़ाते हैं।

वास्तविकता का महत्व बरकरार

मीडिया में वास्तविकता का महत्व बरकरार है हालांकि इसके मायने बदल गए हैं। मीडिया में वर्चुअल रिएलिटी और ऑगमेंटेड रिएलिटी की गूंज हो रही है। वीआर और एआर तकनीक की मदद से दर्शकों को देश में बैठे-बैठे विदेशों में घटने वाली घटनाओं का हिस्सा बनाया जा सकता है। यदि किसी वॉर फ्रंट से घटना पेश की जा रही है तब स्टूडियो में ऐसा माहौल रचा जाता है कि दर्शकों को लगता है कि वह खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं।

मल्टीमीडिया रिपोर्टर

आज दर्शकों को या पाठकों को सुनाई जाने वाली कहानी अखबार के पन्नों से लेकर वीडियो, पॉडकॉस्ट, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स से लेकर वर्चुअल प्लेटफार्म तक अपने पैर पसार चुकी है। इसे दिलकश बनाने को मल्टीमीडिया ऐसी स्टोरी तैयार करते हैं जिसे कई फार्मेट में उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए टैक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। सोशल मीडिया ने इसकी स्वीकार्यता को कई गुना तक बढ़ा दिया है।

संभावनाएं और आमदनी

लगभग सभी स्ट्रीम्स के युवाओं के लिए यह क्षेत्र खुला हुआ है। तकनीकी पक्ष जिसके लिए कम्प्यूटर इंजीनियरिंग, कोडिंग और कम्प्यूटर लैंग्वेजेस का ज्ञान जरूरी है उसे छोड़ कला, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, अभिनय और खानपान का ज्ञान रखने वाले तक इसमें कैरियर बना सकते हैं। कुछ साल पहले मीडिया क्षेत्र केवल रेडियो, टीवी और अखबारों तक ही सीमित था। लेकिन मल्टी मीडिया और सोशल मीडिया ने इसे पंख लगा दिए हैं। मीडिया प्लेटफार्म्स एक्स, व्हाट्सएप,और पॉडकास्ट आदि में कैरियर निर्माण की राहें खुल गई हैं। मीडिया ने नये अवसरों के साथ आय के भी बेहतरीन अवसर प्रदान किए हैं। युवाओं के लिए जरूरी नहीं कि किसी मीडिया हाउस या चैनल की नौकरी कर बंधकर सीमित आय प्राप्त करें। इस क्षेत्र ने योग्य तथा अनुभवी युवाओं को खुद अपना सोशल मीडिया चैनल स्थापित कर या किसी स्थापित चैनल से जुड़ कर अच्छी आय हासिल करने का मौका दिया है। ■

2050 तक भारत में 34 करोड़ होंगे बुजुर्ग

कई चुनौतियां होंगी सामने

भारत में 2050 तक 50 प्रतिशत आबादी शहर में होने का अनुमान है, इसलिए झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है.

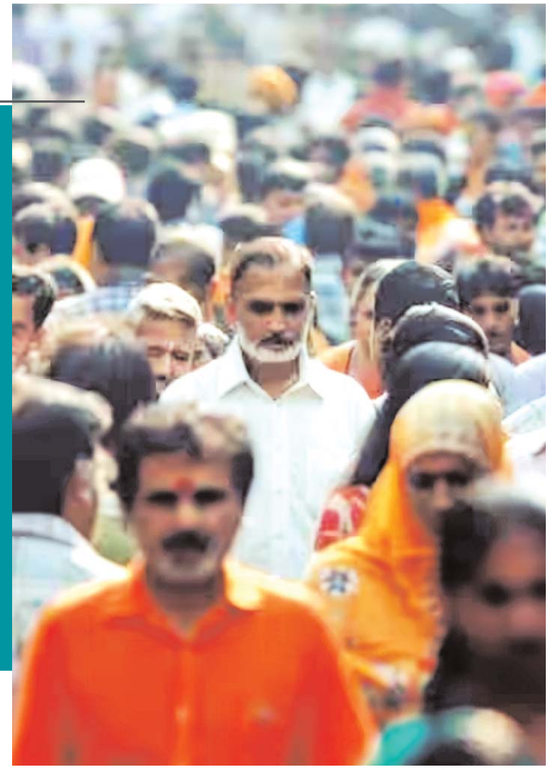

तिलकराज

भारत अभी युवाओं का देश है. देश की ज्यादातर आबादी जवान है, लेकिन 2050 तक स्थिति काफी बदल सकती है. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की भारत इकाई 'यूएनएफपीए-इंडिया' की प्रमुख एंड्रिया वोजनार ने कहा है कि भारत की बुजुर्ग आबादी 2050 तक दोगुनी हो जाने की संभावना है. देश में खासकर उन बुजुर्ग महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन में अधिक निवेश किए जाने की जरूरत है, जिनके 'अकेले रह जाने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है'. 'यूएनएफपीए-इंडिया' की 'रेजिडेंट' प्रतिनिधि वोजनार ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए अपने इंटरव्यू में जनसंख्या के उन प्रमुख रुझानों को रेखांकित किया, जिन्हें भारत सतत विकास में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता दे रहा है. इनमें युवा आबादी, वृद्ध जनसंख्या, शहरीकरण, प्रवासन और जलवायु के अनुसार बदलाव करना शामिल हैं. ये कारक सभी देश के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर पेश करते हैं.

2050 तक 34 करोड़ होंगे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग

वोजनार ने कहा कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या 2050 तक दोगुनी होकर 34 करोड़ 60 लाख हो जाने का अनुमान है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा, आवास और पेंशन योजनाओं में निवेश बढ़ाने की सख्त जरूरत है. उन्होंने कहा, '...खासकर वृद्ध महिलाओं के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जिनके अकेले रहने और गरीबी का सामना करने की अधिक आशंका है.' 'यूएनएफपीए-इंडिया' प्रमुख ने कहा कि भारत में युवा आबादी काफी है और 10 से 19 वर्ष की आयु के 25 करोड़ 20 लाख लोग हैं. उन्होंने जिक्र किया कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी के लिए प्रशिक्षण और रोजगार सृजन में निवेश करने से इस जनसांख्यिकीय क्षमता को भुनाया जा सकता है और देश को सतत प्रगति की ओर अग्रसर किया जा सकता है.

अकेली रहने वाली महिलाओं के सामने खास चुनौतियां

वोजनार ने कहा, भारत में 2050 तक 50 प्रतिशत आबादी शहर में होने का अनुमान है, इसलिए झुग्गी बस्तियों की वृद्धि, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए स्मार्ट शहरों, मजबूत बुनियादी ढांचे और किफायती आवास का निर्माण महत्वपूर्ण है. शहरी योजनाओं में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जरूरतों, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा एवं नौकरियों तक पहुंच को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके. वोजनार ने यह भी कहा कि आंतरिक और बाहरी प्रवासन को प्रबंधित करने के लिए अच्छे से सोच-विचार कर योजना बनाने, कौशल विकास करने और आर्थिक अवसर वितरण की आवश्यकता होती है. उन्होंने कहा कि पति के किसी दूसरे स्थान पर जाने के कारण अकेली रहने वाली महिलाओं या प्रवासी महिलाओं के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों से निपटना संतुलित विकास के लिए जरूरी है.

कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं

जलवायु परिवर्तन के अनुसार बदलाव को विकास योजनाओं में शामिल करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करना भारत के लिए महत्वपूर्ण है. वोजनार ने कहा, जलवायु परिवर्तन प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है जिससे गर्भधारण करना कठिन हो सकता है, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं और आपात स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित हो सकती है. इन मुद्दों से निपटना लैंगिक समानता और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि इन रुझानों पर ध्यान केंद्रित करके भारत अधिक सतत और न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला देश है और उसने काफी प्रगति की है, लेकिन 'कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं.

वोजनार ने कहा, एनएफएचएस-5 (2019-21) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, परिवार नियोजन की 9.4 प्रतिशत जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं और अनियोजित गर्भधारण के 7.5 प्रतिशत मामले हैं. इस वर्ष की 'थीम' विशेषकर उन क्षेत्रों में गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन संसाधनों तक पहुंच में सुधार के प्रयासों का समर्थन करती है जहां इसकी अत्यधिक आवश्यकता है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की 'थीम' के आधार पर ''मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण का उचित समय एवं अंतराल'' के बारे में जागरुकता पैदा करने के प्रयास कर रहा है क्योंकि ये मां और शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं. विशेषज्ञों ने शिशु के जन्म के बाद महिला के फिर से गर्भवती होने के बीच कम से कम 24 महीने का अंतराल रखने की सलाह दी है. इससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम होता है और पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं. ■

(यह खबर सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट 2026 केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण नीति दस्तावेज़ माना जा रहा है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, महंगाई के दबाव और रोजगार की चुनौतियों के बीच प्रस्तुत इस बजट में सरकार ने विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत बनी हुई है और सरकार का फोकस दीर्घकालिक विकास, निवेश और समावेशी प्रगति पर केंद्रित है। बजट 2026 को 'विकासोन्मुखी और भविष्य की नींव रखने वाला बजट' बताया जा रहा है।

मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश

बजट 2026 में मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने के संकेत दिए गए हैं। कर प्रणाली में सुधार से वेतनभोगी वर्ग को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि टैक्स का बोझ कम होता है तो इसका सीधा असर घरेलू खपत पर पड़ेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

रोजगार सृजन और युवाओं पर विशेष जोर

देश की बड़ी युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 में रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है। तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल रोजगार देगा, बल्कि भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।

बजट 2026 में कृषि क्षेत्र को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर बल दिया गया है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि भंडारण, ग्रामीण सड़कों और कृषि-आधारित उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर शहरों की ओर पलायन को कम करना है।

सड़क, रेल, शहरी आवास, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा को बजट 2026 की प्रमुख विशेषताओं में गिना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए सरकार ने सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की रणनीति अपनाई है। इससे न केवल विकास को गति मिलेगी, बल्कि लाखों नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है।

आर्थिक स्थिरता, विकास और आम आदमी की उम्मीदों का संतुलित दस्तावेज़

सामाजिक क्षेत्र और कल्याण योजनाएं

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में भी बजट 2026 में निरंतरता दिखाई देती है। सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की मंशा भी बजट में स्पष्ट दिखती है।

> **"आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि, बजट की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी प्रभावी ढंग से होता है और आम जनता को इसका लाभ कितनी जल्दी मिल पाता है।"**

राजनीतिक और आर्थिक संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया यह बजट सरकार के दीर्घकालिक विज़न को दर्शाता है। समर्थकों का मानना है कि बजट 2026 भारत को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक आर्थिक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है, जबकि विपक्ष ने कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए हैं।

विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, बजट 2026 में विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने का प्रयास किया गया है। हालांकि, बजट की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कितनी प्रभावी ढंग से होता है और आम जनता को इसका लाभ कितनी जल्दी मिल पाता है।

कुल मिलाकर, बजट 2026 को एक ऐसा बजट माना जा रहा है जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास को नई गति देने का प्रयास करता है। अब देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बजट में किए गए वादे जमीन पर कितनी तेजी और ईमानदारी से उतरते हैं।

छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना को लेकर बजट में मिला लगभग साढ़े सात हजार करोड़

7 हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी सेक्टर में डेलीकेटेड कॉरिडोर होंगे

छत्तीसगढ़ में रेलवे परियोजना को लेकर बजट में लगभग साढ़े सात हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. जिसमें 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी सेक्टर में डेलीकेटेड कॉरिडोर होंगे. रायपुर के डीआरएम कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं के विस्तार को लेकर जानकारी दी.

इसमें छत्तीसगढ़ के साथ ही देश के दूसरे राज्यों को भी इस बजट में रेलवे को क्या कुछ मिला यह भी उन्होंने बताया है. छत्तीसगढ़ में रेलवे को 7 हजार 470 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में 24 गुना अधिक है.

रायपुर रेल मंडल को होगा फायदा

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने बताया की देखिए आपने अभी रेल मंत्री जी को सुना. इसमें उन्होंने रेल बजट यानी यूनियन बजट के बारे में स्टेट वाइज जानकारी दी. छत्तीसगढ़ को इस यूनियन बजट में लगभग साढ़े सात हजार करोड रुपए प्रावधान किया गया है. इसके साथ छत्तीसगढ़ में पहले से जो रेल परियोजना चल रही है. वह करीब 51 हजार करोड़ रुपए रुपए का है. पूरी बजट का फोकस इस बार आधारभूत संरचनाओं का विकास है.

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने कहा, इसमें 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भारतीय रेल लाने जा रहा है, जिसमें पहला 7 हाई स्पीड कॉरिडोर के साथ ही पूर्वी सेक्टर में डेलीकेटेड कॉरिडोर होंगे, जो दानकुनी से सूरत को कनेक्ट करेगा. यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी. यह कॉरिडोर ऐसा होगा जो हमारे जितने भी पोर्ट है उसकी भी कनेक्टिविटी होगी. भारत का जो एक्सपोर्ट कनेक्शन है उसका बहुत बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा.

रावघाट जगदलपुर परियोजना स्वीकृत

रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने कहा रावघाट जगदलपुर परियोजना स्वीकृत है. इस परियोजना के तहत रेलवे ने अधिकांश काम पूरा कर लिया है. कुछ कम बचे हुए हैं जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है. यह बहुत ही टारगेटेड प्रोजेक्ट है. इसको लेकर रेल मंत्रालय भी काफी सेंसिटिव है. इस परियोजना को फास्ट ट्रैक से पूरा किया जाएगा.

छत्तीसगढ़ बन रहा रेल सुविधा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य - मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ में रेलवे अधोसंरचना विकास के लिए रू.7,470 करोड़ के ऐतिहासिक बजट प्रावधान किए जाने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आज रेलवे क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2009-14 के दौरान वार्षिक औसत ?311 करोड़ की तुलना में 2026-27 में रू.7,470 करोड़ का बजट प्रावधान लगभग 24 गुना वृद्धि का रिकॉर्ड है। वर्तमान में राज्य में रू.51,080 करोड़ के रेल कार्य प्रगति पर हैं, जिनमें नए ट्रैक निर्माण, स्टेशनों का पुनर्विकास तथा सुरक्षा उन्नयन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सुदूर वनांचल बस्तर में जगदलपुर को जोड़ने वाले रावघाट-जगदलपुर रेल प्रोजेक्ट का प्रारंभ होना बस्तर के जनजातीय समाज के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक अमूल्य उपहार है, जो क्षेत्रीय विकास की नई राह प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परमलकसा-खरसिया कॉरिडोर के साथ-साथ नए फ्रेट कॉरिडोर को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में यात्री गाड़ियों की संख्या आने वाले समय में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें डोंगरगढ़ (फेज-I), अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई और उरकुरा जैसे स्टेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस की 2 जोड़ी तथा अमृत भारत एक्सप्रेस की 1 जोड़ी सेवाएँ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक लगभग 1,200 किलोमीटर नए रेल ट्रैक का निर्माण, 100 प्रतिशत विद्युतीकरण, 170 फ्लाईओवर/अंडरपास तथा 'कवच' जैसी आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना से रेल सुविधा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को इन युगांतकारी पहलों के लिए हृदय से धन्यवाद दिया है।

छत्तीसगढ़ का अनमोल खजाना

293 मिलियन साल पुराने समुद्री जीवाश्मों का राज़ खोलता

गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क

प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर छत्तीसगढ़ में घूमने-फिरने के लिए कई शानदार जगहें हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे बढ़कर राज्य के एक अनमोल खजाने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को जानें।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। यह वह दौर था जब आज का यह भू-भाग एक ठंडे समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। यह जीवाश्म पार्क केवल अतीत की कहानी नहीं बताता बल्कि भारत की भूगर्भीय विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस अनमोल धरोहर को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह स्थान वैज्ञानिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

इस पार्क की खोज 1954 में भूवैज्ञानिक एस.के. घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। इसकी खासियत न सिर्फ इसका विशाल क्षेत्रफल है, बल्कि यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यहां से द्विपटली (बायवेल्व) जीव, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रिनॉइड और ब्रायोज़ोआ जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म तालचिर संरचना से संबंधित हैं, जो पर्मियन युग के शुरुआती दौर को दर्शाते हैं।

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह क्षेत्र समुद्री जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण समुद्र में डूब गया था। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ा और इस क्षेत्र में समुद्री जीवन का जमाव हुआ। बाद में जब जलस्तर घटा तो ये समुद्री जीव चट्टानों में दब गए और लाखों वर्षों में जीवाश्म के रूप में बदल गए।

गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क केवल छत्तीसगढ़ या भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। ऐसे ही जीवाश्म ब्राजील के पराना बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, अंटार्कटिका के अलेक्जेंडर आइलैंड और दक्षिण अफ्रीका के कारू बेसिन में भी पाए गए हैं। यह पार्क गोंडवाना महाद्वीप के भूगर्भीय इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाता है।

बदलते मौसम और मानवीय गतिविधियों के कारण इस जीवाश्म उद्यान को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसे संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अगस्त 2021 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिकों, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इसे राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इस जीवाश्म पार्क के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए 41.99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। पार्क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इसे पर्यटन व अनुसंधान के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ■

सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी की दरकार

टेलीग्राम मैसेजिंग एप पर सक्रिय चैनलों और समूहों के माध्यम से कई तरह के गैरकानूनी कार्यों को मूर्त रुप दिया जा रहा है. इसमें सिनेमा, वेब सीरीज, इ-बुक, सॉफ्टवेयर, हैकिंग सॉफ्टवेयर आदि को बिना अनुमति साझा करना सबसे सामान्य है.

सतीश सिंह

नकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए टेलीग्राम पर वैश्विक स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ऑस्ट्रेलिया की इ-सेफ्टी कमीशन ने मार्च 2024 में यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, टेलीग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग फीचर्स, एल्गोरिदम और रिकमेंडेशन सिस्टम के जरिये चरमपंथी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नोटिस दिया था. कमीशन ने टेलीग्राम से विशेष रूप से पूछा था कि वह बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है? पुनश्च, अगस्त 2024 में टेलीग्राम के संस्थापक श्री पावेल ड्यूरोव को अवैध गतिविधियों में एप के इस्तेमाल के आरोप में फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था. इस वर्ष भी मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को टेलीग्राम पर खरीदा और बेचा जा रहा था. ये उदाहरण महज बानगी भर हैं, इन प्लेटफॉर्म पर किये जा रहे काले कारनामों की लंबी फेहरिस्त है.

टेलीग्राम मैसेजिंग एप पर सक्रिय चैनलों और समूहों के माध्यम से कई तरह के गैरकानूनी कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है. इसमें सिनेमा, वेब सीरीज, इ-बुक, सॉफ्टवेयर, हैकिंग सॉफ्टवेयर आदि को बिना अनुमति साझा करना सबसे सामान्य है. यहां निवेश, लॉटरी या अन्य फर्जी आकर्षक योजनाओं की आड़ में ठगी को अंजाम दिया जाता है. डार्क वेब के जरिये ड्रग्स, अश्लील फोटो व वीडियो, क्रेडिट कार्ड के विवरण आदि की खरीद-फरोख्त की जाती है. यहां फर्जी खबरों, सूचनाओं और अफवाहों का भी प्रचार-प्रसार किया जाता है, जिससे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता फैलने की आशंका रहती है. राजनीतिक दल, व्यक्ति विशेष और कारोबारी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने एजेंडे और विविध उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं. चरमपंथी संगठन भी इसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करते हैं. चूंकि टेलीग्राम स्वतंत्र स्रोत और निजी मैसेजिंग को बढ़ावा देता है, इसलिए, इस पर लगाम लगाना मुश्किल है.

व्हाट्सएप दुनिया का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप है. इसका इस्तेमाल भी अवैध और अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है. व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा होने के कारण गैर-कानूनी कार्यों को अंजाम देना आसान होता है. व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिये अफवाहें और झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं. कोरोना महामारी के दौरान भी वैक्सीन, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं से जुड़ी भ्रामक जानकारी फैला कर लोगों को भ्रमित किया गया था. फर्जी लॉटरी और नौकरी का झांसा, बैंकिंग और ओटीपी धोखाधड़ी, क्रिप्टो में निवेश, झूठी निवेश योजनाओं, केवाइसी अपडेट धोखाधड़ी, सिम ब्लॉक होने आदि मैसेज भेजकर भी धोखाधड़ी की जा रही है. डीपफेक और मॉर्फ्ड फोटो के जरिये भी ठगी हो रही है. डेटिंग स्कैम के तहत लड़कियों के नाम से नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है. फर्जी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना नकली सामानों को बेचा जा रहा है.

स्नैपचैट के डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर का लाभ उठाकर ड्रग, हथियार, और नकली दस्तावेजों की खरीद-फरोख्त की जा रही है. यहां फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करना और फिर उनकी निजी तस्वीरें व वीडियो लीक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना आम हो गया है. अश्लील कंटेंट का स्नैपचैट एक बड़ा अड्डा बन चुका है. यहां पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल सक्रिय है. निजी स्नैप या प्रीमियम स्नैप जैसे कोड वर्ड के जरिये गैरकानूनी तरीके से एडल्ट कंटेंट को यहां खरीदा व बेचा जाता है. वहीं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धोखाधड़ी एवं ठगी के लिए पैसे देकर फॉलोअर, लाइक, कमेंट व व्यूज खरीदे व बेचे जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर फर्जी नौकरी के ऑफर, फर्जी लिंक भेजकर लोगों की निजी जानकारी व बैंक विवरण चुराये जा रहे हैं. आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे नकली पहचान पत्र बेचे जा रहे हैं. ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी की जा रही है. इन प्लेटफॉर्मों पर फर्जी ब्रांड और ऑनलाइन स्टोर भी सक्रिय हैं, जो सस्ती दर पर उत्पाद बेचने का लालच देकर ठगी को अंजाम देते हैं.

यूट्यूब भी ठगी का बड़ा माध्यम है. यहां भी गैर-कानूनी कंटेंट और अश्लील रील दिखाये जा रहे हैं. साथ ही, सब्सक्राइबर, व्यूज और लाइक खरीदे व बेचे जा रहे हैं. पायरेसी और कॉपीराइट उल्लंघन, फर्जी गुरु, फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर सभी इस चैनल पर ठगी की दुकान चला रहे हैं. कई यूट्यूब चैनल भ्रामक खबरें, अफवाह और झूठे दावे फैलाकर करोड़ों व्यूज एवं पैसे कमाते हैं. धर्म, राजनीति और समाज से जुड़े विवादास्पद कंटेंट बनाकर भी पैसे कमाये जा रहे हैं. कई तरह के झूठे दावे किये जाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य सबसे प्रमुख है.

सरकार मैसेजिंग एप और सोशल मीडिया के जरिये हो रहे काले कारनामों से वाकिफ है, पर अभी तक कोई ऐसा कानून या उपाय लेकर हमारे समक्ष नहीं आ पायी है, जिससे आमजन को इन परेशानियों से मुक्त कराया जा सके. ऐसे में यूजर्स को ही सावधान रहने की जरूरत है. नाबालिगों के संदर्भ में माता-पिता की जिम्मेदारी बदले परिवेश में बढ़ गयी है. उन्हें हर समय सतर्क रहने, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने और उनके कार्य-कलापों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है. ■

आधुनिक घोटुल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा

मुख्यमंत्री ने घोटुल की स्थापत्यकला को सराहा

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने दो दिवसीय नारायणपुर प्रवास के दौरान 'गढ़बेंगाल घोटुल' पहुंचकर बस्तर की गौरवशाली परंपराओं और लोक-संस्कृति के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इस मौके पर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की मधुर ध्वनि और ग्रामीणों के आत्मीय स्वागत के बीच मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं लोक-रंग में रंगे नजर आए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल की अनूठी स्थापत्य कला का अवलोकन किया और बस्तर की विभूतियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि घोटुल प्राचीन काल से ही आदिवासी समाज के लिए शैक्षणिक एवं संस्कार केंद्र रहा है। चेंद्रु पार्क के समीप स्थित यह आधुनिक घोटुल न केवल नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ेगा, बल्कि देश-दुनिया के पर्यटकों को भी आदिवासी जीवनशैली और सामाजिक व्यवस्था से परिचित कराने का सशक्त माध्यम बनेगा। गढ़बेंगाल का यह घोटुल हमारी गौरवशाली विरासत को सहेजने का प्रतीक है। हमारी सरकार बस्तर की इस अनूठी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने घोटुल परिसर के लेय्योर एवं लेयोस्क कुरमा- युवाओं और युवतियों के लिए निर्मित कक्षों के साथ ही बिडार कुरमा- पारंपरिक वेशभूषा, प्राचीन वाद्ययंत्र एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का संग्रह का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों की आग्रह पर मुख्यमंत्री श्री साय ने सगा कुरमा में बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेकर क्षेत्र की खान-पान संस्कृति का सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री के भोजन में विशेष रुप से भोजन गाटो-भात, कोदो-भात, उड़िद दार, हिरुवा दार, जीरा भाजी, कनकी पेज, भाजी धिरोल फुल, चाटी भाजी, कांदा भाजी, मुनगा भाजी, इमली आमट, मड़िया पेज, टमाटर चटनी, चिला रोटी, रागी कुरमा, रागी केक, रागी लड्डू, रागी जलेबी परोसा गया।

इस दौरान वन मंत्री श्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष श्री रुपसाय सलाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नारायण मरकाम, पद्मश्री श्री पंडीराम मंडावी, लोककलाकार श्री बुटलू राम, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि श्रीमती संध्या पवार ने साथ बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया।

बस्तर की विभूतियों से आत्मीय भेंट

मुख्यमंत्री ने इस प्रवास को केवल एक औपचारिक दौरा न रखते हुए इसे एक आत्मीय मिलन का रुप दिया। क्षेत्र की महान प्रतिभाओं - वैद्यराज पद्मश्री हेमचंद मांझी, पद्मश्री पंडीराम मंडावी और सुप्रसिद्ध लोक-कलाकार बुटलू राम से भेंट कर उनका सम्मान किया। उन्होंने टाइगर ब्वॉय चेंदरु के परिवारजनो से भी मुलाकात की।

इको-फेंडली घोटुल

वन विभाग और पद्मश्री पंडीराम मंडावी के मार्गदर्शन में निर्मित यह घोटुल पूर्णतः इको-फेंडली (लकड़ी, मिट्टी और बांस) सामग्री से बना है। मुख्यमंत्री ने घोटुल के खंभों पर की गई बारीक नक्काशी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की, जिसे स्वयं पद्मश्री पंडीराम मंडावी ने उकेरा है। जिसमें नक्काशी, सांस्कृतिक जुड़ाव, विरासत का संरक्षण का प्रभावी प्रयास किया गया है।

संविधान, लोकतंत्र और सुशासन के रास्ते विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण सरकार का संकल्प

भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक आस्था, समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है।

लोकतंत्र की मजबूती, संविधान की सर्वोच्चता और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ 77वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास, देशभक्ति और गौरवपूर्ण वातावरण में मनाया गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। उन्होंने शहीद सैनिकों एवं पुलिस जवानों के परिजनों को सम्मानित किया तथा छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत का संविधान हमारी लोकतांत्रिक आस्था, समानता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार है। छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा, विकास और समृद्धि के लिए राज्य सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने गणतंत्र दिवस संदेश में राज्य की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं, नक्सल उन्मूलन की दिशा में हुई प्रगति, किसानों-श्रमिकों-महिलाओं के सशक्तीकरण, शिक्षा-स्वास्थ्य-औद्योगिक विकास और सुशासन की विस्तार से जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करने का दिन भी है। उन्होंने संविधान निर्माताओं, विशेषकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए कहा कि संविधान सामाजिक समरसता, समान अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक है। उन्होंने बाबा गुरु घासीदास जी के मनखे-मनखे एक समान के संदेश को संविधान की आत्मा बताया और कहा कि भारतीय गणतंत्र ने ऐसा खुला समाज निर्मित किया है, जहां हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने हाल ही में राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा गठित इस राज्य ने 25 वर्षों में विकास की सशक्त यात्रा तय की है। उन्होंने बताया कि संविधान के मंदिर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से संपन्न हुआ। धान की बालियों की डिजाइन और बस्तर-सरगुजा की लोककला से सुसज्जित यह भवन छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150वीं जयंती राज्यभर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। सुकमा जिले के कोंटा से लेकर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के सीतामढ़ी हरचौका तक लोगों ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को सच्ची श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन का उल्लेख करते हुए कहा कि जनजातीय समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकार्पित शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डिजिटल संग्रहालय देश का पहला डिजिटल संग्रहालय है, जो आज की पीढ़ी को जनजातीय नायकों के बलिदान से परिचित कराता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि माओवादी हिंसा लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ ने निर्णायक रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि जवानों के अदम्य साहस और सतत अभियानों के परिणामस्वरूप माओवादी हिंसा अब अंतिम चरण में है और मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सलमुक्त करने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास, बस्तर कैफे जैसी पहलों और नियद नेल्ला

नदी-नालों के किनारे रहने वालों को कैंसर का खतरा अधिक

आईसीएमआर ने 11 मार्च को राज्यसभा को बताया कि 2024 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि नदी नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा बहुत अधिक है, और कई खतरे सीमा से ऊपर पाए गए हैं

भारत में बढ़ती जनसंख्या के बीच रहने के लिए जमीन की कमी हो रही है। ऐसे में लोग अक्सर नदी और नालों के किनारे की जमीन पर ही अपना घर बना लेते हैं और रहने लगते है। भारत के कई बड़े शहरों में जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, यहां कई बड़े-छोटे नालों के किनारे लोगों के बड़े घर है। हालांकि, ऐसी जगहों पर रह रहे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजी है क्योंकि आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नदी-नालों के किनारे रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारी का खतरा अधिक है।

11 मार्च को राज्यसभा को सूचित किया गया कि एक अध्ययन से पता चला है कि नदी नालों के पास रहने वाले लोगों में कैंसर का खतरा काफी अधिक है, और कई खतरे के गुणांक सीमा से ऊपर पाए गए हैं।अध्ययन से पता चला है कि सीसा, लोहा और एल्यूमीनियम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक हैं।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा, एक पहल के तहत, 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) को उन्नत निदान और उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए मंजूरी दी गई है। जाधव ने कहा कि कैंसर देखभाल सेवाओं को और बढ़ाने के लिए हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर स्थापित किया गया है।

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत कैंसर का इलाज भी कवर किया जाता है, जो माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक प्रदान करता है। उन्होंने दावा किया कि इस योजना से आबादी के निचले 40 प्रतिशत हिस्से के लगभग 55 करोड़ लोगों (12.37 करोड़ परिवार) को लाभ मिलता है। हाल ही में, पीएमजेएवाई ने आय की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार किया। इस योजना में 200 से अधिक पैकेज शामिल हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लाभ पैकेज के भीतर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और उपशामक चिकित्सा से संबंधित 500 से अधिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।

इसके अलावा, केंद्र ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) शुरू की है 28 फरवरी, 2025 तक, देश भर में कुल 15,057 पीएमबीजेके खोले गए, जो सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे थे। जाधव ने कहा कि इस योजना में 2,047 प्रकार की दवाएँ और 300 सर्जिकल उपकरण सूचीबद्ध हैं, जिनमें 87 उत्पाद विशेष रूप से कैंसर के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। एमओएस ने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सस्ती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी) पहल का उद्देश्य कैंसर, हृदय रोगों और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है।

31 जनवरी, 2025 तक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 222 अमृत फार्मेसियां थीं, जो बाज़ार दरों पर 50 प्रतिशत तक की छूट पर कैंसर की दवाओं सहित 6,500 से अधिक दवाएं दे रही थीं। जाधव ने कहा कि कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) से निपटने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) लागू किया जा रहा है।

कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान और प्रबंधन पर केंद्रित है। एनपी-एनसीडी के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 6,410 एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के जरिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरिए कैंसर के निवारक पहलू को मजबूत किया जा रहा है।

जाधव ने कहा कि एनपी-एनसीडी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उल्लिखित कैंसर सहित एनसीडी से संबंधित जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। ■

कचरा प्रबंधन में कोताही

अदालत ने कहा कि सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं प्रगति पर हैं. परंतु, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन के बगैर शहर स्मार्ट कैसे रह सकते हैं?

सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर सुनवाई के दौरान 2016 में लागू किये गये ठोस कचरा प्रबंधन नियम के पूर्णतः अनुपालन की जो जरूरत बतायी है, उसे समझा जाना चाहिए. उसने कहा है कि कचरा जहां से निकल रहा है, वहीं उसे अलग करना पर्यावरण के लिए जरूरी है. कचरे को अलग किये बगैर सीधे संयंत्रों में भेजने से अधिक प्रदूषण होता है. वैसे में, कचरे से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाएं भी अधिक प्रदूषण फैलायेंगी.

अदालत ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का हवाला देते हुए कहा कि इसका पालन न करने से सभी शहर प्रभावित हुए हैं. वर्ष 2016 में लागू किये गये इस नियम के तहत अपशिष्ट प्रबंधन में विभिन्न परिवर्तन किये गये हैं, जिसमें पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अपशिष्ट के न्यूनीकरण, पुनर्चक्रण और प्रबंधन के संबंध में विभिन्न हितधारकों पर जिम्मेदारियां लागू करना शामिल है. लेकिन अभी ज्यादातर शहरों से कूड़ा बाहर निकाल कर उसे कहीं और डंप कर दिया जाता है, जो पर्यावरण के हित में नहीं हैं.

अदालत ने कहा कि सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं प्रगति पर हैं. परंतु, ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन के बगैर शहर स्मार्ट कैसे रह सकते हैं? चूंकि इस मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब है, इसे देखते हुए पीठ ने एनसीआर में ठोस कचरा प्रबंधन नियम के अमल पर राज्यों को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा है.

जाहिर है, अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन में नियमों का अनुपालन नहीं किया गया, तो देशभर के दूसरे शहरों में कूड़ों के निपटान में व्याप्त बदइंतजामी को कैसे दूर किया जा सकेगा? ■

विस अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 10 एकड़ में निर्मित पत्रकार आवासीय परिसर के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में हुए शामिल

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज 10 एकड़ में निर्मित पत्रकार आवासीय परिसर के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 3 करोड़ 79 लाख 91 हजार रूपए की लागत से पत्रकार आवासीय परिसर का लोकार्पण किया तथा परिसर में 49 लाख रूपए की लागत से पानी टंकी सम्पवेल एवं पाईप लाईन विस्तार कार्य के लिए भूमिपूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि संस्कारधानी राजनांदगांव का गौरवशाली इतिहास रहा है और आज उसी में क्रम एक नया नाम जुड़ रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रकार कॉलोनी में लोकर्पण एवं भूमिपूजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव संस्कारधानी से उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां और ताकत मिली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि राजनांदगांव के पत्रकारों की मेहनत, परिश्रम और एकजुटता से पत्रकार कॉलोनी का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के लिए राजनांदगांव के पत्रकारों की एकजुटता एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका मकान होता है। 141 पत्रकारों को अपना आवास मिलेगा। पत्रकार गणतंत्र को पोषित, पल्लिवत करने वाले कलम के जादूगर होते हैं। यहां रानी सूर्यमुखी देवी के नाम से आवासीय परिसर होगा। उन्होंने सभी को पत्रकार कालोनी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने दो हाई मास्ट लाईट एवं एक सड़क के निर्माण कराने की बात कही।

वरिष्ठ पत्रकार श्री हिमांशु द्विवेदी ने कहा कि पत्रकार बिरादरी के सामूहिक प्रयासों और शासकीय सहयोग से आवास का सपना पूरा हुआ। संस्कारधानी राजनांदगांव के पत्रकारों ने एकजुटता का परिचय देते हुए छत्तीसगढ़ में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक साथ रहकर जीवन संवार सकते है। यहां पानी, बिजली सहित अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी है। औद्योगिक प्रतिष्ठान एबीस के प्रमुख एवं समाजसेवी श्री बहादुर अली ने कहा कि आज का दिन खुशी का दिन है, जहां 141 पत्रकार एक साथ रहने वाले है। उन्होंने कहा कि ऐसे पत्रकार जिनका आवास तीन वर्ष में पूर्ण होगा, उनके घर में एबीस की ओर से एयर कंडिशनर की सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारिता के संबंध पारिवारिक संबंधों में बदल जाएंगे।

प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री सचिन अग्रहरि ने आवासीय परिसर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय, समझ के साथ सकारात्मकता से यह कार्य संभव हो सका है। साहित्य, संस्कृति एवं कला की त्रिवेणी संस्कारधानी में एक नया अध्याय जुड़ा है। जहां सभी के सहयोग से कलम के पुजारियों को एक ही परिसर में अपने एवं अपने परिवार के लिए जीवन भर के सपने को साकार करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रेस क्लब हाऊसिंग सोसायटी के अध्यक्ष श्री मिथलेश देवांगन ने कहा कि पत्रकार आवासीय परिसर लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम के अविस्मरणीय पलों के सभी साक्षी बने है। पानी, बिजली एवं अन्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तेजी से कार्य किया जा रहा है और छह महीने में कालोनी पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। इस अवसर पर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल श्री नीलू शर्मा, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद श्री प्रदीप गांधी, श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री सुरेश एच लाल, श्री जितेन्द्र मुदलियार, प्रेस क्लब के संरक्षक श्री जितेन्द्र मिश्रा, श्री अशोक पाण्डेय, श्री सुशील कोठारी, प्रेस क्लब हाऊसिंग सोसायटी के पूर्व अध्यक्ष श्री अतुल श्रीवास्तव, प्रेस क्लब के सचिव श्री अनिल त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष श्री बसंत शर्मा, सहित पत्रकारगण और परिवारजन उपस्थित थे। आभार प्रदर्शन श्री विरेन्द्र बहादुर ने किया।

नार योजना के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों की जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अन्नदाता की समृद्धि रही है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को धान का देश में सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। बीते दो वर्षों में किसानों के खातों में डेढ़ लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। अटल सिंचाई योजना के तहत 115 लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और प्रतिदिन लगभग 2 हजार आवासों का निर्माण हो रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य विद्युत उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और शीघ्र ही प्रथम स्थान की ओर अग्रसर है। सौर ऊर्जा, गैस आधारित परियोजनाओं और शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किए जाने की जानकारी दी। अब तक 14,948 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने श्रमिकों के लिए ईएसआई, श्रम संहिताओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही।

मुख्यमंत्री ने बताया कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षकों की कमी दूर की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, 9 हजार स्मार्ट क्लास और 22 हजार कंप्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नए मेडिकल कालेजों की स्वीकृति से अब इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 7.83 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नवा रायपुर को आईटी, एआई, फार्मा और मेडिकल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य एआई का है और छत्तीसगढ़ इसकी धुरी बनेगा।

मुख्यमंत्री ने रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, बस्तर पंडुम, चित्रकोट जलप्रपात, मैनपाट, सरगुजा और जशपुर पर्यटन के विकास का उल्लेख किया। उन्होंने ई-ऑफिस, जेम पोर्टल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की मजबूती पर बल दिया।

समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां निकाली गईं, जिन्होंने प्रदेश की विकास यात्रा को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया।

विकसित छत्तीसगढ़ का आह्वान

मुख्यमंत्री ने स्व. लक्ष्मण मस्तूरिया जी की कविता की पंक्तियों के माध्यम से जनभागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने अंत में प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।

अंतरिक्ष केंद्र बनेगी युवा सपनों को पूरा करने की प्रयोगशाला

हर बच्चें का अंतरिक्ष यात्रा का सपना होगा पूराः ग्रुप कैप्टन शुभांशु

मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का किया शुभारंभ

अंतरिक्ष केंद्र युवा सपनों को पूरा करने की प्रयोगशाला बनेगी। यह केंद्र प्रदेश के वैज्ञानिक भविष्य की मजबूत नींव है और पूरे प्रदेश में अंतरिक्ष केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के राखी में जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के तहत आयोजित अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम में ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के साथ छत्तीसगढ़ के पहले अंतरिक्ष केंद्र का विधिवत शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में अंतरिक्ष संगवारी पहल को विस्तार देते हुए सभी जिलों में अंतरिक्ष केंद्र खोले जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन एवं अंतरिक्ष यात्री डॉ. शुभांशु शुक्ला का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि डॉ. शुभांशु शुक्ला जैसे व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं, जिनकी अंतरिक्ष यात्रा ने देश को गौरवान्वित किया है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद करते हुए कहा कि आज से उनके सपनों को पंख मिल रहे हैं और उनका आकाश और भी बड़ा हो गया है। यह अंतरिक्ष केंद्र केवल एक भवन नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों की प्रयोगशाला है, जहां वे विज्ञान को किताबों से बाहर निकालकर प्रयोग और अनुसंधान के माध्यम से समझ सकेंगे। उन्होंने जशपुर जिले के बच्चों द्वारा रॉकेट निर्माण की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि यह उदाहरण बताता है कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उचित अवसर की होती है, जिसे यह केंद्र उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान अब केवल जिज्ञासा का विषय नहीं, बल्कि रोजगार और करियर का बड़ा क्षेत्र बन चुका है। इसरो की वैश्विक विश्वसनीयता के कारण भारत आज अंतरिक्ष की दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में यह केंद्र बच्चों को सैटेलाइट निर्माण, ट्रैकिंग, मौसम पूर्वानुमान, क्लाउड मैपिंग जैसे आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रशिक्षण देगा। उन्होंने कहा कि इस अंतरिक्ष केंद्र से किसानों को सटीक मौसम और फसल संबंधी जानकारी मिलेगी, जिससे कृषि को सीधा लाभ होगा। साथ ही, तकनीक आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं का महानगरों की ओर पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सैटेलाइट तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और भविष्य में इस क्षेत्र में स्पेस साइंस का महत्व और बढ़ेगा।

छत्तीसगढ़ के बच्चों में अपार क्षमता और जिज्ञासा-ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला

ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा लगती है और कुछ ही समय में शून्य से लगभग 30 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष तक पहुंचा जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को ऊर्जावान प्रदेश बताते हुए कहा कि यहां के बच्चों में अपार क्षमता और जिज्ञासा है। उन्होंने मुख्यमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ बच्चों को स्पेस साइंस से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम है। उन्होंने कहा कि क्लीन स्टेशन के उद्घाटन के दौरान मैंने देखा कि मुख्यमंत्री स्टेशन में प्रवेश से पहले स्वयं विशेष ड्रेस व कैप को पहन रहे थे। मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि राज्य का मुखिया जब स्वयं ऐसी रुचि दिखाता है, तो यह बच्चों और युवाओं के भविष्य को लेकर उनकी स्पष्ट और भविष्योन्मुखी सोच को दर्शाता है।

अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 5 सितंबर 2025 को प्रदेश के विद्यार्थियों से हुए ऑनलाइन संवाद का उल्लेख करते

राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली

संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य सरकार ने राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करते हुए वरिष्ठ और अनुभवी आईपीएस अधिकारी IPS संजीव शुक्ला को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। यह फैसला न केवल राजधानी की कानून-व्यवस्था को नई दिशा देगा, बल्कि शहरी पुलिसिंग को आधुनिक, प्रभावी और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर माना जा रहा है।

तेजी से बढ़ती आबादी, महानगर की ओर बढ़ता रायपुर, ट्रैफिक का दबाव, साइबर अपराध, नशे का नेटवर्क और संगठित अपराध—इन तमाम चुनौतियों के बीच कमिश्नरेट व्यवस्था को समय की मांग बताया जा रहा था। अब इस व्यवस्था के लागू होने से राजधानी की पुलिसिंग पूरी तरह नए ढांचे में काम करेगी।

नई व्यवस्था के तहत रायपुर जिले को दो भागों में बांटा गया है - रायपुर अर्बन और रायपुर रूरल. रायपुर अर्बन पुलिस जिला कमिश्नरेट सिस्टम के अंतर्गत काम करेगा, जबकि रायपुर रूरल पुलिस जिला एसपी के अधीन रहेगा.

रायपुर अर्बन में कुल 21 थाना क्षेत्र हैं, जिन्हें सेंट्रल, वेस्ट और नॉर्थ जोन में बांटा गया है. वहीं रायपुर रूरल में विधानसभा, धरसीवां, खरोरा समेत अन्य क्षेत्र आते हैं, जिनकी जिम्मेदारी एक पुलिस अधीक्षक के पास होगी.

इस नए सिस्टम में पुलिस कमिश्नर, डीसीपी और एसीपी को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के अधिकार भी दिए गए हैं. इसके साथ ही उन्हें जिले के कई कानूनों के तहत जिला मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी.

सरकार का कहना है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्र की संयुक्त आबादी लगभग 19 लाख है. बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते अपराध की चुनौतियों को देखते हुए कमिश्नरेट सिस्टम को लागू किया गया है.

क्या है पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली

पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) को कई मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होते हैं। इससे किसी भी आपात स्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो जाती है।

अब कानून-व्यवस्था से जुड़े कई मामलों में पुलिस को सीधे कार्रवाई करने की शक्ति मिलेगी, जिससे अपराधियों पर त्वरित शिकंजा कसना संभव होगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्रणाली बड़े महानगरों—दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद—में पहले से लागू है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। रायपुर में इसे लागू करना राजधानी के महानगर बनने की दिशा में एक और संकेत है।

सरकार का संदेश-राजधानी में सख्त लेकिन संवेदनशील पुलिसिंग

राज्य सरकार के इस निर्णय के पीछे साफ संदेश है— अपराध पर जीरो टॉलरेंस, कानून-व्यवस्था में तेजी और पारदर्शिता, जनता के प्रति जवाबदेह पुलिस तंत्र, सरकार ने एक ऐसे अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी है, जो फील्ड एक्सपीरियंस के साथ-साथ प्रशासनिक संतुलन और निर्णय क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

रायपुर पुलिस के सामने नई चुनौतियां

राजधानी रायपुर आज केवल प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और स्टार्टअप का उभरता हब बन चुका है।

ऐसे में पुलिस के सामने चुनौतियां भी बहुआयामी हैं— बढ़ता ट्रैफिक दबाव, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन अपराध, महिला सुरक्षा, नशा तस्करी. संगठित अपराध और अवैध गतिविधियाँ। कमिश्नरेट प्रणाली और अनुभवी नेतृत्व के साथ इन चुनौतियों से निपटने की उम्मीदें कहीं अधिक बढ़ गई हैं।

पुलिस कमिश्नर के रूप में प्राथमिकताएं

सूत्रों के अनुसार, IPS संजीव शुक्ला की प्राथमिकताओं में शामिल हैं—

- महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता
- स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
- साइबर क्राइम पर विशेष यूनिट का सशक्तिकरण
- बीट सिस्टम को मजबूत कर पुलिस-जन संवाद बढ़ाना
- थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता

इसके साथ ही, राजधानी को सेफ सिटी मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।

आईपीएस संजीव शुक्ला

अनुशासन, अनुभव और नेतृत्व का नाम

आईपीएस संजीव शुक्ला छत्तीसगढ़ कैडर के उन वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कठिन से कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व किया है। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में रही है, जो कानून की सख्ती और मानवीय संवेदनशीलता—दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलते हैं।

अब तक का प्रशासनिक सफर

भारतीय पुलिस सेवा में चयन के बाद उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में अहम जिम्मेदारियाँ निभाईं। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती के दौरान कानून-व्यवस्था को स्थिर करने और आम जनता में भरोसा कायम करने में अहम भूमिका निभाई। बतौर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन्होंने अपराध नियंत्रण, खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने और अंतर-जिला समन्वय पर विशेष काम किया। साइबर अपराध, संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई के लिए वे जाने जाते हैं। ट्रैफिक सुधार, सीसीटीवी निगरानी, आधुनिक पुलिस ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उनके अधीन काम कर चुके अधिकारी बताते हैं कि वे डिसिप्लिन के साथ संवाद को सबसे बड़ा हथियार मानते हैं।

जनता की उम्मीदें

रायपुर के नागरिकों में इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को उम्मीद है कि कमिश्नरेट व्यवस्था और नए नेतृत्व से— अपराध पर लगाम लगेगी, पुलिस कार्रवाई तेज होगी, आम आदमी को थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

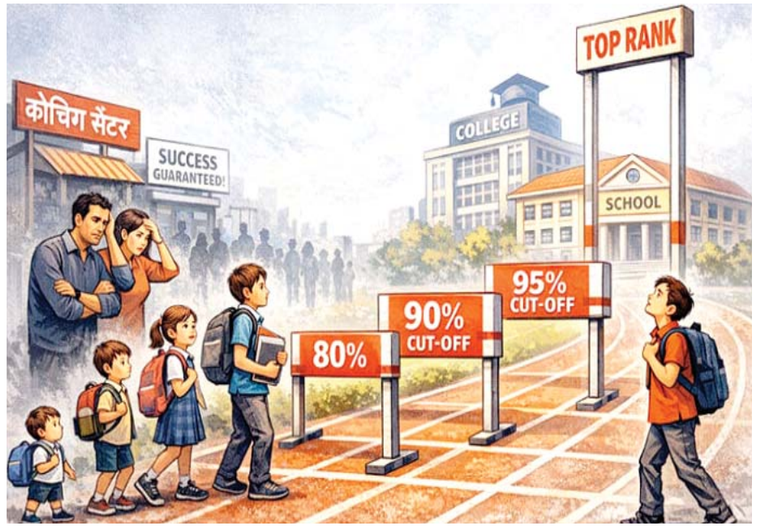

नर्सरी से कॉलेज तक, एडमिशन की युद्धभूमि

कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल-कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है–जिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है।

आज शिक्षा का अर्थ सीखना नहीं, बल्कि साबित करना हो गया है। साबित करना कि बच्चा बेहतर है, तेज़ है, दूसरों से आगे है। और यह साबित करने की ज़िम्मेदारी बच्चे से ज़्यादा उसके माता-पिता के कंधों पर डाल दी गई है। नतीजा यह है कि नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, 'दाखिला' अब एक सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक तनाव का कारण बन चुका है।

दाखिले की इस दौड़ में सबसे पहले निशाने पर आता है मासूम बच्चा। वह उम्र, जब खेलना, कल्पना करना और सवाल पूछना चाहिए, उसी उम्र में उसे फ़ॉर्म, इंटरव्यू, टेस्ट और रैंक के बोझ तले दबा दिया जाता है। नर्सरी एडमिशन के नाम पर माता-पिता छुट्टियाँ लेते हैं, स्कूल-दर-स्कूल भटकते हैं, सिफ़ारिशें ढूँढते हैं और कई बार आत्मसम्मान तक गिरवी रख देते हैं। यह सब इसलिए नहीं कि बच्चा सीख सके, बल्कि इसलिए कि वह 'अच्छे स्कूल' का टैग हासिल कर सके।

आज शिक्षा संस्थान ज्ञान के मंदिर कम और प्रतिस्पर्धी बाज़ार ज़्यादा बनते जा रहे हैं। अख़बारों में 'मिशन एडमिशन' जैसे शब्द आम हो चुके हैं। टीवी चैनलों पर दाखिले को लेकर बहसें होती हैं, कोचिंग संस्थान भविष्य की गारंटी बेचते हैं और स्कूल-कॉलेज अपनी ब्रांड वैल्यू चमकाने में लगे रहते हैं। इस पूरे तंत्र में बच्चा एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट बन जाता है—जिसे हर हाल में सफल दिखाना ज़रूरी है।

कभी 60-65 प्रतिशत अंक लाना सम्मान की बात हुआ करती थी। सेकंड डिविज़न जीवन की हार नहीं मानी जाती थी। आज हालात यह हैं कि 90 प्रतिशत से नीचे अंक लाने वाला बच्चा और उसके माता-पिता अपराधबोध में जीते हैं। 95-96 प्रतिशत अंक लाने वालों को भी चैन नहीं है, क्योंकि कट-ऑफ़ हर साल नई ऊँचाई छू रहा है। ऐसा लगता है मानो अंकों की इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं।

यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब ज़्यादातर बच्चे 90 प्रतिशत से ऊपर अंक ला रहे हैं, तो क्या वास्तव में सब असाधारण प्रतिभाशाली हैं? या फिर मूल्यांकन प्रणाली ही अपना संतुलन खो चुकी है? शिक्षा का उद्देश्य समझ विकसित करना था, लेकिन वह अब अंकों और रैंक के गणित में सिमट कर रह गया है। ज्ञान से ज़्यादा प्रदर्शन मायने रखता है, और प्रदर्शन से ज़्यादा उसका प्रचार।

इस पूरी प्रक्रिया का सबसे भयावह पहलू है बच्चों पर पड़ने वाला मानसिक दबाव। परीक्षा, इंटरव्यू और चयन की अनिश्चितता बच्चे के भीतर डर और असुरक्षा पैदा करती है। असफलता की स्थिति में पहला सवाल यही होता है—'अब क्या होगा?' यह सवाल सिर्फ़ भविष्य का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का भी होता है। बच्चा यह मानने लगता है कि उसकी असफलता उसके माता-पिता की हार है। यह भाव उसके आत्मविश्वास को गहरे तक चोट पहुँचाता है।

विडंबना यह है कि माता-पिता भी इस दबाव के शिकार हैं। समाज ने उनके सामने सफलता की एक संकीर्ण परिभाषा रख दी है—टॉप स्कूल, टॉप कॉलेज और टॉप करियर। वे यह सोचने से डरते हैं कि अगर उनका बच्चा इस तय ढाँचे में फिट नहीं हुआ, तो लोग क्या कहेंगे। परिणामस्वरूप वे बच्चे की रुचि, क्षमता और स्वभाव को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त असमानता इस समस्या को और गंभीर बना देती है। जिनके पास संसाधन हैं, वे महँगी कोचिंग, प्राइवेट स्कूल और मैनेजमेंट कोटा खरीद सकते हैं। लेकिन मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चों के लिए यह दौड़ कहीं ज़्यादा कठिन है। योग्यता के बावजूद अवसर न मिलना, व्यवस्था पर से भरोसा तोड़ देता है। धीरे-धीरे शिक्षा सामाजिक न्याय का माध्यम न रहकर विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाती है।

एक और चिंताजनक पहलू यह है कि हम बच्चों को सोचने के बजाय रटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सवाल पूछने वाले बच्चे 'डिस्ट्रैक्टेड' माने जाते हैं और उत्तर याद करने वाले 'मेधावी'। रचनात्मकता, संवेदनशीलता और नैतिकता जैसे गुण पाठ्यक्रम से बाहर कर दिए गए हैं। शिक्षा का लक्ष्य इंसान बनाना था, लेकिन हम मशीन तैयार करने में लगे हैं।

इस संदर्भ में यह सवाल बेहद ज़रूरी है—क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ़ टॉपर पैदा करना है? या ऐसे नागरिक तैयार करना है जो समाज के प्रति ज़िम्मेदार हों, सवाल पूछ सकें और बदलाव ला सकें? जब तक हम इस सवाल का ईमानदारी से उत्तर नहीं खोजेंगे, तब तक दाख़िले की यह दौड़ और ज़्यादा बेरहम होती जाएगी।

ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को बाज़ार से मुक्त किया जाए और मूल्यांकन प्रणाली को मानवीय बनाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, गुणवत्ता सुधारने और अवसरों को समान बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास हों। सबसे ज़रूरी है माता-पिता और समाज की सोच में बदलाव—कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और सफलता का एक ही रास्ता नहीं होता। अगर शिक्षा को आनंद, जिज्ञासा और आत्मविकास का माध्यम बना दिया जाए, तो दाखिले की यह दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी। वरना हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा भविष्य सौंपेंगे, जहाँ डिग्रियाँ तो होंगी, लेकिन संतुलन और संवेदनशीलता नहीं।

आज ज़रूरत इस बात की है कि हम रुककर सोचें—क्या शिक्षा का मक़सद केवल टॉपर पैदा करना है, या संवेदनशील, सोचने-समझने वाला इंसान बनाना? जब तक दाख़िले की यह अंधी दौड़ जारी रहेगी, तब तक शिक्षा बोझ बनी रहेगी, आनंद नहीं। बदलाव सिस्टम में चाहिए, लेकिन शुरुआत हमारी सोच से होगी—वरना यह दौड़ हर साल और बेरहम होती जाएगी।

हुए कहा कि उस दौरान छत्तीसगढ़ के एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आपने सब कुछ बताया, लेकिन यह बताइए कि प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया होमवर्क आपने पूरा किया या नहीं। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न बच्चों की तीक्ष्ण बुद्धि और बारीक नजर को दर्शाता है।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अपने अंतरिक्ष मिशन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब आप रॉकेट पर बैठते हैं, तो आपको लगता है कि आप पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जैसे ही रॉकेट इग्नाइट होता है, वह क्षण इतना शक्तिशाली होता है कि सारी तैयारी एक पल के लिए भूल जाते हैं। उन्होंने इसकी तुलना परीक्षा से करते हुए कहा कि जैसे पढ़ाई पूरी होने के बाद भी परीक्षा कक्ष में प्रश्नपत्र सामने आते ही कुछ क्षणों के लिए सब कुछ खाली लगने लगता है, ठीक वैसी ही अनुभूति अंतरिक्ष यात्रा के समय होती है। ऐसे समय में संयम रखना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।

अंतरिक्ष में 20 दिनों के प्रवास के दौरान पृथ्वी की 320 बार परिक्रमा की

ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने कहा कि 41 वर्षों के बाद भारत ने दोबारा अंतरिक्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और यह यात्रा केवल उनकी नहीं, बल्कि पूरे भारत की यात्रा थी। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में 20 दिनों के प्रवास के दौरान उन्होंने पृथ्वी की 320 बार परिक्रमा की और लगभग 1.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की। अंत में उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार परिश्रम करने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री श्री साय ने डॉ. शुभांशु शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बच्चों से आह्वान किया कि वे बड़े सपने देखें, विज्ञान से दोस्ती करें और छत्तीसगढ़ का नाम देश-दुनिया में रोशन करें। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि अंतरिक्ष यात्री डॉ. शुभांशु शुक्ला को अपने बीच पाकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने देश के युवाओं को नई दिशा दी है और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।

वन एवं संसदीय कार्य मंत्री व जिला के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि यह पहल सरकार की दूरदर्शी सोच का परिचायक है, जो आने वाली पीढ़ी को भविष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के भीतर असीम क्षमता और शक्ति है, जो आपके सपनों को साकार करेगी। अंतरिक्ष विज्ञान जैसे जटिल विषय को सरल और सहज तरीके से समझाने के लिए किए जा रहे प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं। मंत्री श्री कश्यप ने बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को मजबूत करने के साथ-साथ वैज्ञानिक सोच को भी प्रोत्साहित करते हैं। श्री शुक्ला को डीपीएस, सैनिक स्कूल राजनांदगांव के बच्चों ने पोटरेट भेंट किया।

कार्यक्रम में विधायक श्री मोतीलाल साहू, विधायक श्री अनुज शर्मा, विधायक श्री इंद्र कुमार साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री संदीप यदु, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, निगम आयुक्त श्री विश्वदीप सहित गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चें मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला के साथ आज नवा रायपुर के राखी में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर के बच्चों द्वारा तैयार रॉकेट का बटन दबाकर प्रक्षेपण किया।

जशक्राफ्ट को मिला राष्ट्रीय पहचान का नया मंच

महिलाओं द्वारा बांस, छिंद, मिट्टी एवं लकड़ी से बनाए उत्पाद मिलेंगे देश के विभिन्न एयरपोर्ट पर

मुख्यमंत्री साय के समक्ष रेयर प्लेनेट संस्था से हुआ ऐतिहासिक एमओयू

वन विभाग की पहल पर जशपुर जिले में महिला सशक्तिकरण और वन आधारित आजीविका को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में विगत दिवस बगिया में रेयर प्लेनेट संस्था तथा जशपुर जिले की स्व-सहायता समूह—जागरण, स्माईल आरती, राखी एवं मुस्कान समूह—के मध्य जशक्राफ्ट ब्रांड के उत्पादों के विपणन हेतु अनुबंध समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।इस महत्वपूर्ण समझौते के अंतर्गत अब जशपुर की जनजातीय महिलाओं द्वारा बांस, छिंद, मिट्टी एवं लकड़ी से निर्मित हस्तशिल्प, आभूषण एवं सजावटी उत्पाद देश के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर संचालित रेयर प्लेनेट के बिक्री केंद्रों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। इससे स्थानीय स्व-सहायता समूहों को स्थायी बाजार, उचित मूल्य तथा नियमित आय के अवसर प्राप्त होंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एमओयू को जशपुर की महिलाओं के लिए एक निर्णायक उपलब्धि बताते हुए कहा कि जशक्राफ्ट जैसे ब्रांड के माध्यम से हमारी आदिवासी बहनों की कला अब देशभर के लोगों तक पहुँचेगी। यह पहल केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतंत्रता और स्वावलंबन की मजबूत नींव रखती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निरंतर प्रयास है कि वन एवं परंपरागत ज्ञान आधारित आजीविका को बाजार से जोड़ा जाए, ताकि महिलाएं अपने गांव में रहकर सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह एमओयू 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' की अवधारणा को साकार करता है तथा जशपुर की जनजातीय महिलाओं को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक ठोस और दूरगामी पहल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, पत्थलगांव क्षेत्र की विधायक श्रीमती गोमती साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, कलेक्टर श्री रोहित व्यास, वनमंडलाधिकारी श्री शशि कुमार सहित स्व-सहायता समूह की महिलाएं एवं रेयर प्लेनेट संस्था के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

पुस्तक विमोचन और जशक्राफ्ट उत्पादों की सराहना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा जशक्राफ्ट पर आधारित विशेष पुस्तक का विमोचन किया गया। उन्होंने जशक्राफ्ट के अंतर्गत तैयार किए गए आभूषणों एवं हस्तनिर्मित उत्पादों का अवलोकन करते हुए उनकी गुणवत्ता, कलात्मकता और नवाचार की सराहना की।

स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी एवं विधायक श्रीमती गोमती साय का जशक्राफ्ट ब्रांड के पारंपरिक आभूषण पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया, जो महिला सशक्तिकरण और स्थानीय संस्कृति के सम्मान का सशक्त प्रतीक बना।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री द्वारा जशक्राफ्ट ब्रांड के प्रचार-प्रसार हेतु तैयार वीडियो का भी विमोचन किया गया, जिससे जशक्राफ्ट को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान मिलने की उम्मीद है।

जशक्राफ्टः जशपुर की सांस्कृतिक विरासत से जन्मा सशक्त ब्रांड

उल्लेखनीय है कि जशक्राफ्ट जशपुर जिले की समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत की सजीव अभिव्यक्ति है। जिले की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या जनजातीय समुदायों से आती है, जहाँ पीढ़ियों से बाँस, कांसा घास, छिंद पत्ते, लकड़ी एवं मिट्टी से हस्तनिर्मित कलाकृतियाँ तैयार की जाती रही हैं। पूर्व में संगठित व्यवस्था और बाजार की कमी के कारण कारीगरों की प्रतिभा सीमित रह जाती थी।

जिला प्रशासन की पहल से जशक्राफ्ट के रूप में ऐसा सशक्त मंच विकसित हुआ है, जो जशपुर जिले के आठों विकासखंडों के कारीगरों को एकजुट कर उनकी कला को पहचान, संरक्षण और बाजार उपलब्ध करा रहा है।

इस पहल के केंद्र में आदिवासी महिला कारीगर हैं, जिनके हाथों से बिना मशीनों के बने उत्पाद परंपरा, प्रकृति और आत्मनिर्भरता का संदेश देते हैं। जशक्राफ्ट आज स्वदेशी ज्ञान से आकार लेते हुए एक टिकाऊ और सम्मानजनक आजीविका मॉडल के रूप में उभर रहा है।

वन विभाग द्वारा संचालित यह पहल महिला स्वावलंबन, वन आधारित आजीविका और स्थानीय उत्पादों के राष्ट्रीय बाजारीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो रही है, जो आने वाले समय में जशपुर को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय मानचित्र पर विशिष्ट पहचान दिलाएगी।

शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे।

इसके बावजूद वे उन नेताओं में रहे जो फाइलों से नहीं, फैसलों से पहचाने जाते थे।

उपमुख्यमंत्री के रूप में उनका सफर महाराष्ट्र की राजनीति में एक अनोखा अध्याय है। छह बार इस पद तक पहुंचना केवल राजनीतिक संयोग नहीं था, बल्कि सत्ता संतुलन, गठबंधन राजनीति और संगठनात्मक ताकत का परिणाम था। वे सरकार में अक्सर संकटमोचक की भूमिका में दिखे। बजट, वित्तीय प्रबंधन और संसदीय रणनीति में उनकी पकड़ ऐसी थी कि विरोधी भी उनके अनुभव को नजरअंदाज नहीं कर पाते थे। उन्हें महत्वाकांक्षी कहा गया, कभी-कभी कठोर और रूखे स्वभाव का नेता भी बताया गया, लेकिन यह भी सच है कि सत्ता की वास्तविकता को वे भावनाओं से नहीं, निर्णयों से देखते थे। विवाद उनके राजनीतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे। सिंचाई घोटाले से लेकर बयानबाजी तक, कई मौके ऐसे आए जब उनकी छवि पर प्रश्नचिह्न लगे। 'अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके भरें?' जैसे बयान ने उन्हें आलोचनाओं के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने माफी भी मांगी, सफाई भी दी और समय के साथ उन विवादों से उबरते हुए फिर सत्ता के शीर्ष पर लौटे। यह उनकी राजनीतिक जिजीविषा का प्रमाण था कि आलोचना और आरोप उन्हें रोक नहीं पाए।

शरद पवार के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी हमेशा चर्चाएं रहीं। कभी मतभेद, कभी दूरी और कभी सियासी अलग राह की अटकलें। लेकिन अजित पवार स्वयं को हमेशा शरद पवार का अनुयायी बताते रहे। उन्हें मिला 'दादा' का संबोधन केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि वह एक राजनीतिक ब्रांड बन चुका था, जो उनके समर्थकों में भरोसे और नेतृत्व की भावना जगाता था। वे संगठनकर्ता भी थे और प्रशासक भी, रणनीतिकार भी और जमीनी नेता भी।

उन्हें अपनी विविध आयामी भूमिकाओं से अपने को मिले 'दादा' के अलंकरण को सार्थक भी किया और जीवंतता भी दी। उनका असामयिक निधन एक क्रूर विडंबना है। जिस नेता ने दशकों तक सत्ता की उड़ान भरी, उसकी जीवन यात्रा एक विमान हादसे में थम गई। कहा जाता है कि दुर्घटना से कुछ समय पहले तक वे पूरी तरह सक्रिय थे, योजनाओं, बैठकों और राजनीतिक समीकरणों में व्यस्त। यह अचानक आई मृत्यु उस अनिश्चितता को रेखांकित करती है, जो सत्ता और जीवन दोनों के साथ जुड़ी है।

अजित पवार का व्यक्तित्व एवं कृतित्व सफल राजनेता, समाज निर्माता, ग्राम-उद्धारक, सहकारी आन्दोलन पुरोधा, कुशल प्रशासक के रूप में अनेक छवि, अनेक रंग, अनेक रूप में उभरकर सामने आता हैं। आपके जीवन की दिशाएं विविध एवं बहुआयामी थीं। आपके जीवन की धारा एक दिशा में प्रवाहित नहीं हुई, बल्कि जीवन की विविध दिशाओं का स्पर्श किया।

यही कारण है कि कोई भी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आपके जीवन से अछूता रहा हो, संभव नहीं लगता। आपके जीवन की खिड़कियाँ समाज एवं राष्ट्र को नई दृष्टि देने के लिए सदैव खुली रही। उनकी सहजता और सरलता में गोता लगाने से ज्ञात होता है कि वे राजनीतिक सरोकार से ओतप्रोत एक अल्हड़ एवं साहसिक व्यक्तित्व थे। बेशक अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन अपने जुझारु राजनीति जीवन के दम पर वे हमेशा भारतीय राजनीति एवं राष्ट्रवादी सोच के आसमान में एक सितारे की तरह टिमटिमाते रहेंगे।

आज जब महाराष्ट्र और देश उनके निधन पर शोकाकुल है, तब अजित पवार का मूल्यांकन केवल प्रशंसा या आलोचना के तराजू पर नहीं किया जा सकता। वे विवादों से घिरे रहे, लेकिन उनसे परिभाषित नहीं हुए। उनकी राजनीति कठोर थी, लेकिन उसमें अनुभव की गहराई थी। वे लोकप्रियता से अधिक प्रभाव में विश्वास रखते थे। शायद यही कारण है कि उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सन्नाटा है, जिसे शब्दों में बांधना कठिन है।

अजित पवार का जीवन यह सिखाता है कि राजनीति केवल भाषणों और नारों से नहीं चलती, बल्कि निर्णय, जोखिम और जिम्मेदारी से चलती है। उनका जाना एक चेतावनी भी है और एक स्मृति भी, क्योंकि सत्ता क्षणभंगुर है, लेकिन अनुभव और प्रभाव लंबे समय तक याद किए जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में 'दादा' के नाम से पहचाना जाने वाला यह व्यक्तित्व अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उसकी छाया आने वाले वर्षों तक राज्य की राजनीति पर बनी रहेगी।

अजित पवार

आरोपों से ऊपर उठे राजनीति के 'दादा'

28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया।

यह खबर केवल एक व्यक्ति के निधन की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के एक पूरे युग के अचानक थम जाने की सूचना है। 28 जनवरी 2026 की सुबह जब बारामती में हुए विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार के असामयिक निधन की पुष्टि हुई, तो वह क्षण केवल पवार परिवार के लिए नहीं, बल्कि समूचे महाराष्ट्र और देश की राजनीति के लिए गहरे शोक और स्तब्धता का कारण बन गया। जिस नेता को लोग अधिकार, अनुभव और निर्णय क्षमता का पर्याय मानते थे, उसका इस तरह अचानक चले जाना सत्ता, प्रशासन और राजनीतिक संतुलन में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है। एक संभावनाओं भरी महाराष्ट्र की राजनीति एवं राष्ट्रीय विचारों का सफर ठहर गया, उनका निधन न केवल महाराष्ट्र के लिये, भारत की राष्ट्रवादी सोच के लिये बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी राजनीति पर एक गहरा आघात है, अपूरणीय क्षति है। उनके निधन से सहकारी आन्दोलन को भी गहरा धक्का लगा है।

अजित पवार का जीवन किसी राजसी विरासत की सहज कहानी नहीं था। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देओली प्रवरा क्षेत्र में जन्मे अजित पवार ने जीवन को बहुत करीब से संघर्ष करते हुए देखा। उनके पिता अनंतराव पवार फिल्म जगत से जुड़े रहे, राजकमल स्टूडियो में काम किया, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां साधारण रहीं। औपचारिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही सीमित रही, किंतु जीवन की व्यावहारिक पाठशाला ने उन्हें वह सिखाया जो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थान भी नहीं सिखा पाते। शायद यही कारण रहा कि अजित पवार की राजनीति किताबों से नहीं, जमीन से निकली हुई राजनीति थी, जिसमें किसानों की पीड़ा, सहकारी संस्थाओं की ताकत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नब्ज साफ दिखाई देती थी। राजनीति में उनका प्रवेश किसी बड़े मंच से नहीं, बल्कि सहकारी आंदोलन की प्रयोगशाला से हुआ। 1982 में मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने एक चीनी सहकारी संस्था का चुनाव लड़ा। यह वही दौर था जब महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी संस्थाएं सत्ता की रीढ़ मानी जाती थीं। अजित पवार ने बहुत जल्दी समझ लिया कि यदि ग्रामीण महाराष्ट्र को साधना है तो उसे बैंक, चीनी मिल, सिंचाई और बिजली से जोड़ना होगा। यही समझ आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बनी।

1991 अजित पवार के राजनीतिक जीवन का निर्णायक वर्ष रहा। पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने वित्तीय प्रशासन और संगठन संचालन में अपनी दक्षता का परिचय दिया। सोलह वर्षों तक इस पद पर बने रहना अपने आप में उनकी विश्वसनीयता और पकड़ को दर्शाता है। उसी वर्ष बारामती से लोकसभा के लिए निर्वाचित होना उनके बढ़ते कद का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। यह फैसला केवल पारिवारिक निष्ठा का नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरदृष्टि का भी उदाहरण था। इसके बाद विधानसभा में प्रवेश और फिर लगातार बारामती से जीत ने उन्हें जनाधार का वह आधार दिया, जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में विरले ही कोई चुनौती दे सका। अजित पवार को सत्ता के गलियारों में पहुंचाने वाली सबसे बड़ी विशेषता उनकी प्रशासनिक पकड़ थी। कृषि, बागवानी, बिजली और जल संसाधन जैसे कठिन और संवेदनशील विभागों को संभालते हुए उन्होंने विकास और विवाद दोनों को नजदीक से जिया। जल संसाधन मंत्री के रूप में कृष्णा घाटी और कोकण सिंचाई परियोजनाओं से उनका नाम जुड़ा। इन परियोजनाओं ने जहां किसानों के लिए पानी और उम्मीद का संदेश दिया, वहीं आलोचनाओं और आरोपों का बोझ भी उनके कंधों पर रखा।

प्रदूषण फैलाते छत्तीसगढ़ के मेडिकल हब

अस्पतालों को हम जीवन का आख़िरी भरोसा मानते हैं। लेकिन सवाल यह है—अगर वही अस्पताल हवा, पानी और ज़मीन को ज़हर बना रहे हों तो इलाज किसका हो रहा है और बीमारी किसकी फैल रही है? आज प्रदेश के कई हिस्सों में अस्पताल बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को केवल फाइलों तक सीमित रखे हुए हैं। इस्तेमाल की गई सिरिंज, खून से सने पट्टे, दवाइयों की एक्सपायरी बोतलें—सब कुछ एक ही कचरे में। नतीजा यह कि संक्रमण अस्पताल की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज में फैल रहा है। यह सिर्फ़ प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, यह संरचनात्मक अनैतिकता है। जिस डॉक्टर की शपथ 'जीवन बचाने' की होती है, उसी व्यवस्था के भीतर पर्यावरण को मारने का मौन अपराध चल रहा है।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को विकास का संकेत माना जाता है। नए अस्पताल, नए मेडिकल कॉलेज, नई मशीनें—सब कुछ आधुनिकता की भाषा बोलता है। लेकिन इस विस्तार के साथ-साथ पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी सिकुड़ती चली गई। चमकदार इमारतों की छाया में एक कड़वी सच्चाई दबी हुई है—इलाज के नाम पर पर्यावरण को ज़हर बनाया जा रहा है। यह कोई भावनात्मक आरोप नहीं। यह निष्कर्ष RTI से प्राप्त दस्तावेज़ों, सरकारी आंकड़ों और ज़मीनी हालात से निकलता है। छत्तीसगढ़ के शहरी केंद्र—रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, कोरबा—आज राज्य के मेडिकल हब बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है— इन अस्पतालों से रोज़ निकलने वाले बायो-मेडिकल कचरे का वैज्ञानिक निपटान कौन कर रहा है?

छत्तीसगढ़ पहले ही औद्योगिक प्रदूषण और कोयला आधारित परियोजनाओं का बोझ झेल रहा है।ऐसे में अस्पतालों से निकलने वाला जहरीला कचरा इस बोझ को और भारी कर रहा है।फर्क बस इतना है—फैक्ट्रियों से निकलता धुआँ दिखता है, लेकिन अस्पतालों से निकलता ज़हर अदृश्य होता है। और जो प्रदूषण दिखता नहीं, वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है।

RTI के जवाब बताते हैं—

- **कई अस्पतालों के पास वैध बायो-मेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन नहीं है . न ही वर्षों से वार्षिक रिपोर्ट जमा की और**

कुछ तो बिना नवीनीकरण के ही संचालित

यानी नियम मौजूद हैं, लेकिन पालन इच्छा पर निर्भर है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार— प्रतिदिन टन के हिसाब से बायो-मेडिकल वेस्ट उत्पन्न हो रहा है मगर CBWTF (कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी) या तो कम हैं,या पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहीं . नतीजा—

कचरा सामान्य कचरे में , खुले में या अवैध रूप से जलाया/दफनाया जा रहा है और यह सिर्फ़ पर्यावरण ही नहीं, जनस्वास्थ्य को भी संक्रमित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए यह अपराध इसलिए भी गंभीर है क्योंकि—

- राज्य पहले से औद्योगिक प्रदूषण झेल रहा है
- कई इलाके भूजल पर पूरी तरह निर्भर हैं
- स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच समान नहीं

ऐसे में अस्पतालों की लापरवाही दो

पीढ़ियों को प्रभावित करती है। यह प्रदूषण केवल हवा में नहीं, बल्कि नालियों, ज़मीन और पानी के रास्ते गाँवों तक फैलता है। जब अस्पताल खुद को 'सेवा' की जगह 'उद्योग' मानने लगते हैं, तब पर्यावरण पहला शिकार बनता है। अब समय आ गया है कि—

- अस्पतालों को भी उद्योगों की तरह पर्यावरणीय ऑडिट के दायरे में लाया जाए
- नागरिक समाज इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े
- प्रशासन 'स्वास्थ्य सेवा' के नाम पर चल रहे इस प्रदूषण को अपराध की तरह देखे

क्योंकि- जो इलाज के नाम पर ज़हर फैलाए, वह अस्पताल नहीं—सिस्टम की बीमारी है।

शासन-प्रशासन की चुप्पी : समस्या की गहरी जड़

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि नियम बनाने वाला और पालन करवाने वाला शासन-प्रशासन अक्सर पीछे हटता है— राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग—तीनों के बीच जिम्मेदारी बंटी हुई है, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं। निरीक्षण अक्सर सूचना देकर होते हैं, जुर्माने नाममात्र के होते हैं,और रिपोर्टें फाइलों में दफन हो जाती हैं। विडंबना यह है कि जिन अस्पतालों के पास प्रभाव, विज्ञापन बजट और राजनीतिक पहुँच है— वही नियमों को सबसे अधिक तोड़ते पाए जाते हैं। छोटे नर्सिंग होम पर कार्रवाई हो जाती है, बड़े संस्थान 'प्रबंधन सुधार' के नाम पर बच निकलते हैं। यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, संस्थागत संरक्षण का मामला है।

बड़े अस्पताल जिनके पास राजनीतिक पहुँच, विज्ञापन बजट और प्रभाव है, वे नियम तोड़ते हैं। छोटे नर्सिंग होम पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े संस्थान 'प्रबंधन सुधार' के बहाने बच निकलते हैं। यानी केवल अस्पताल की लापरवाही नहीं, शासन-प्रशासन की उदासीनता भी समस्या की जड़ है। सिस्टम जानता है, देखता है— लेकिन टकराने से बचता है।

छत्तीसगढ़ को 'हेल्थ मॉडल स्टेट' बनाना है, तो—

- सभी अस्पतालों का सार्वजनिक पर्यावरण अनुपालन डैशबोर्ड
- रीयल-टाइम BMW ट्रैकिंग सिस्टम
- नियम तोड़ने वाले अस्पतालों के नाम सार्वजनिक करना
- CBWTF की संख्या और क्षमता का जिला-स्तरीय विस्तार
- 'स्वास्थ्य सेवा' की आड़ में प्रदूषण को दंडनीय अपराध मानना

और प्रशासन को अब काग़ज़ी औपचारिकताओं से बाहर निकलकर, सख़्त कार्रवाई करने की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। छत्तीसगढ़ को अगर भविष्य सुरक्षित करना है, तो इलाज सिर्फ़ मरीज़ों का नहीं—अस्पतालों की व्यवस्था, मानसिकता और प्रशासनिक रवैये का भी करना होगा। क्योंकि जो आज उपचार के नाम पर ज़हर फैलाता है, वह कल पूरे राज्य की स्वास्थ्य विरासत को खतरे में डाल देगा।

जांच की श्रंखला जारी है .....

नक्सलगढ़ में गूंजा राष्ट्रगान

नियद नेल्लानार के 10 दुर्गम गांवों में आजादी के बाद पहली बार लहराया तिरंगा

बस्तर की सुदूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे उन गांव जहाँ दशकों तक सिर्फ खौफ का साया था, आज राष्ट्रगान की गूँज सुनाई दी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और गृहमंत्री श्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में सुकमा जिले के 10 अति-संवेदनशील गांवों में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया। यह केवल एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि नक्सलवाद पर लोकतंत्र की निर्णायक जीत का शंखनाद है।

सुकमा के दुर्गम अंचलों के नियद नेल्लानार के गांव तुमालभट्टी, वीरागंगलेर, मैता, पालागुड़ा, गुंडाराजगुंडेम, नागाराम, वंजलवाही, गोगुंडा, पेदाबोडकेल और उरसांगल में पहली बार गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। सुरक्षा बलों की सतत तैनाती और नवीन कैंपों की स्थापना ने वह सुरक्षा घेरा प्रदान किया, जिसके कारण ग्रामीण दशकों के भय को त्यागकर मुख्यधारा से जुड़ने आगे आए।

प्रशासन की सक्रियता से इन गांवों में प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित हुई है। बुजुर्गों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ तिरंगे को सलामी दी। ग्रामीणों की आँखों में सुरक्षित भविष्य की चमक इस बात का प्रमाण है कि शासन की 'विश्वास आधारित नीति' रंग ला रही है। सुरक्षा कैंपों के माध्यम से जवानों ने न केवल क्षेत्र को सुरक्षित किया, बल्कि ग्रामीणों का मित्र बनकर उनका दिल भी जीता।

पूना मारगेम (नया रास्ता) से बदलता हुआ सुकमा

छत्तीसगढ़ सरकार का अभियान पूना मारगेम (गोंडी भाषा में जिसका अर्थ है नया रास्ता) अब हकीकत बनता दिख रहा है। सुदूर वनांचलों में तिरंगे का लहराना इस बात की पुष्टि करता है कि अब सुकमा में बंदूक की गूँज नहीं, बल्कि विकास और शांति की लहर चलेगी। जिला प्रशासन और पुलिस बल की इस साझा प्रतिबद्धता ने बस्तर में विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है।

अबूझमाड़ के जाटलूर में पहली बार लहराया तिरंगा

अबूझमाड़ के दुर्गम जंगल क्षेत्र में पहली बार आईटीबीपी के सहयोग से देश का 77वां गणतंत्र दिवस जाटलूर घाटी के जाटलूर गांव में उत्साह और आत्मीय वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कमांडेंट श्री रोशन सिंह असवाल के नेतृत्व में ई-सीओबी जाटलूर के कमांडर सहायक कमांडेंट श्री राम कुमार मौर्य द्वारा किया गया।

इस अवसर पर स्कूल के बच्चों एवं ग्रामीणों के साथ तिरंगा फहराया गया तथा सभी को मिठाइयां वितरित की गईं। इसके बाद आईटीबीपी कैंप परिसर में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जाटलूर एवं हारवेल गांव के 150 से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की और एक साथ भोजन का आनंद लिया। इस पहल से क्षेत्र में खुशी और अपनत्व का माहौल देखने को मिला।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से ई-सीओबी जाटलूर की स्थापना आईटीबीपी द्वारा हाल ही में की गई है। कैंप स्थापित होने के बाद से स्थानीय ग्रामीण धीरे-धीरे देश की मुख्यधारा से जुड़ने लगे हैं। आईटीबीपी द्वारा ग्रामीणों को नि:शुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही कैंप के सामने पेयजल स्टॉल और बैठने की व्यवस्था भी की गई है, जिससे दूरदराज से आने वाले लोगों को राहत मिल रही है।

मास्टर प्लान विकसित किया जा रहा है।

चित्रकोट ग्लोबल डेस्टिनेशन डेवलपमेंट

चित्रकोट इंडिजिनस नेचर रिट्रीट नामक एक व्यापक प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य चित्रकोट को एक वैश्विक स्तर पर पुनर्विकसित करना है। इस परियोजना हेतु पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार से 250 करोड़ रूपए की फंडिंग अपेक्षित है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन का राष्ट्रव्यापी प्रचार

पर्यटन सचिव ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने स्पेन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में आयोजित वैश्विक यात्रा कार्यक्रमों में भाग लेकर छत्तीसगढ़ पर्यटन का देश-विदेश मे भी प्रचार-प्रसार किया, जिससे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को वैश्विक मानचित्र पर भी जगह मिली। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने फिक्की जैसी संस्थाओं के साथ भी भागीदारी की है, जिससे देश के प्रमुख प्रचार मंचों और कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। यूनिवर्सल ट्रैवल कॉन्क्लेव जैसी प्रसिद्ध यात्रा प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

राज्य में पर्यटन से संबंधित व्यवसायों के पंजीकरण में तेजी से वृद्धि

छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 तक टूर ऑपरेटर व ट्रेवल ऑपरेटरों की संख्या मात्र 30 थी, वर्तमान में यह संख्या 300 से अधिक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त 15 होटल छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ पंजीकृत है, जिसकी और अधिक बढ़ने की संभावना है। रिसॉर्टस और मोटल की परिचालन दक्षता और रणनीतिक प्रबंधन के कारण छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का वित्तीय लाभ वित्त वर्ष 2024-25 में जहां 2 करोड़ रूपए था, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में लाभ पांच गुना बढ़कर 10 करोड़ रूपए हो गया है।

छत्तीसगढ़ पर्यटन से स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार, 500 नए होमस्टे विकसित करने का लक्ष्य

सचिव डॉ. रोहित यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ की पर्यटन नीति 2026 के तहत अगले पांच वर्षों में 350 करोड़ रूपए. से अधिक के निवेश का अनुमान है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल लीजकम डेवलपमेंट मॉडल के तहत 17 पर्यटन संपत्तियों को निजी भागीदारी से आउटसोर्स कर 200 करोड़ रूपए का निवेश आकर्षित करने की योजना बना रही है, जिससे सैकड़ों स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। राज्यभर में 500 नए होमस्टे विकसित करने का लक्ष्य है। इसी तरह चित्रकोट में टेंट सिटी के विकास की योजना है, जिसके तहत चित्रकोट फॉल्स के पास साहसिक गतिविधियों के साथ कम से कम 50 लक्जरी टेंट लगाए जाएंगे। फिक्की के सहयोग से छत्तीसगढ़ ट्रैवल मार्ट नामक एक वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम स्थापित किया जाएगा। यह आयोजन बीटूबी पर्यटन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होगा, जिसके तहत भारतीय राज्यों के 200 से अधिक टूर ऑपरेटरों को आकर्षित करने योजना है।

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की उपलब्धियां

संस्कृति एवं पुरातत्त्व के संचालक श्री विवके आचार्य ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के कलाकारों, साहित्यकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन किया जा रहा है, जिससे विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके। उन्होंने बताया कि चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत 141 कलाकारों एवं साहित्यकारों को वित्तीय वर्ष-2024-25 में लगभग 34 लाख रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 130 कलाकारों को लगभग 31 लाख रूपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की गई। इसी तरह कलाकार कल्याण कोष योजना के अंर्तगत कलाकारों और साहित्यकारों अथवा उनके परिवार के सदस्यों की बीमारी, दुर्घटना एवं मृत्यु की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 08 अर्थाभाव ग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को 2 लाख रूपए एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 44 प्रकरणों हेतु 14 लाख रूपए स्वीकृत किया गया है। राज्य शासन छत्तीसगढ़ के कलाकारों एवं साहित्यकारों के प्रत्येक सुख-दुख में साथी है, तथा संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकारों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।

बस्तर पंडुम

छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए किया जा रहा है। यह उत्सव तीन चरणों में 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगा। जनजातीय नृत्य, लोकगीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेश-भूषा-आभूषण, पूजा पद्धति, हस्तशिल्प, चित्रकला, जनजातीय पेय, पारंपरिक व्यंजन, क्षेत्रीय साहित्य, वन-आधारित औषधीय ज्ञान, पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ेगी।

पुरातत्व क्षेत्र की उपलब्धियां

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व स्थित ग्राम रीवां (रीवांगढ़) में चल रहे पुरातात्विक उत्खनन ने प्रदेश के प्राचीन इतिहास को लेकर नई और महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी है। संस्कृति विभाग के पुरातत्त्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा कराए जा रहे इस उत्खनन में वैज्ञानिक ए.एम.एस. रेडियोकार्बन (कार्बन-14) डेटिंग के माध्यम से यह प्रमाणित हुआ है कि इस क्षेत्र में मानव सभ्यता उत्तर वैदिक काल यानी 800 ईसा पूर्व से भी पहले विकसित हो चुकी थी।

भारत भवन विविध कला एवं सांस्कृतिक केन्द्र, राज्य अभिलेखागार, राजकीय मानव संग्रहालय एवं स्वामी विवेकानंद स्मारक संग्रहालय की स्थापना की योजना है।

पर्यटन बना छत्तीसगढ़ का आर्थिक इंजन, संस्कृति बनी पहचान

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की

छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्त्व श्री विवेक आचार्य ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दो वर्षों की उपलब्धियों तथा आगामी कार्ययोजनाओं का विस्तृत विवरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और विरासत संवर्धन तीनों क्षेत्रों में समन्वित प्रगति का मॉडल स्थापित किया है।

पर्यटन विभाग- निवेश, रोजगार और वैश्विक पहचान की ओर तेज़ कदम

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से निजी निवेश के नए द्वार खुले। राज्य और देश के प्रमुख शहरों में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से 500 करोड़ रुपये से अधिक निजी निवेश सुनिश्चित किया गया। इससे पर्यटन अधोसंरचना, होटल, रिसॉर्ट और साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रामलला दर्शन योजना के तहत आईआरसीटीसी के साथ हुए समझौते के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में लगभग 42 हजार 500 श्रद्धालुओं को विशेष ट्रेनों से अयोध्या दर्शन कराया गया। यह योजना धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई होम-स्टे नीति लागू की गई। 500 नए होम-स्टे विकसित करने का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने 24 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ होम-स्टे नीति 2025-30 को अधिसूचित किया है। यह नीति राज्य भर में नए होम-स्टे के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जो ग्रामीण और समुदाय आधारित पर्यटन का समर्थन करती है, इसके लिए राज्य सरकार ने बजट भी स्वीकृत किया है।

फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर- 350 करोड़ की परियोजना

डॉ. रोहित यादव ने बताया कि भारत सरकार की राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत एकीकृत फिल्म सिटी और कन्वेंशन सेंटर के विकास की मंजूरी मिली है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 350 करोड़ रूपए है। भूमि पूजन 24 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के करकमलों से हुई है। यह छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय फिल्म निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में एक नई पहचान मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से छत्तीसगढ़ न केवल फिल्म निर्माण और सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा, बल्कि यह परियोजना राज्य की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी नई गति प्रदान करेगी। चित्रोत्पला फिल्म सिटी और ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण से स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, निवेश के नए अवसर सृजित होंगे और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त होगी। यह परियोजना आने वाले वर्षों में राज्य के युवाओं, कलाकारों और पर्यटन क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खोलेगी।

भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर परियोजना

संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्त्व श्री विवेक आचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना लगभग 146 करोड़ रुपये की लागत से वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित की जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एक जनवरी 2026 को भारत के पर्यटन मंत्री श्री गजेन्द्र शेखावत एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना का भूमिपूजन किया। भोरमदेव मंदिर लगभग एक हजार वर्ष पुरानी ऐतिहासिक धरोहर है और इस कॉरिडोर निर्माण के माध्यम से आने वाले हजार वर्षों तक इसे संरक्षित रखने का कार्य किया जा रहा है।

मयाली-बगीचा विकास, सिरपुर एकीकृत विकास का मास्टर प्लान तैयार

भारत सरकार ने जशपुर में मयाली-बगीचा सर्किट अंर्तगत तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं। इस परियोजना का भूमिपूजन 25 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया था। सिरपुर एकीकृत विकास सिरपुर को एक विश्व विरासत स्थल में बदलने के लिए एक

कर्तव्य पथ पर गूंजा छत्तीसगढ़ के जनजातीय शौर्य का इतिहास

देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की भव्य झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत छत्तीसगढ़ की झांकी ने देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। 'स्वतंत्रता का मंत्र -वंदे मातरम्' थीम पर आधारित यह झांकी जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की गौरवगाथा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती नजर आई।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्रियों और विशिष्ट अतिथियों ने झांकी को उत्सुकता के साथ देखा और तालियां बजाकर सराहना की। दर्शक दीर्घा में मौजूद लाखों लोगों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ छत्तीसगढ़ की झांकी का स्वागत किया। झांकी के समक्ष छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक लोक नृत्य ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया।

झांकी में नवा रायपुर अटल नगर में स्थापित देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय की झलक दिखाई गई, जहां छत्तीसगढ़ सहित देश के 14 प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता आंदोलनों को आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। इस ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती के अवसर पर किया था।

झांकी के अग्र भाग में वर्ष 1910 के ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह के नायक वीर गुंडाधुर को दर्शाया गया। धुर्वा समाज के इस महान योद्धा ने अन्यायपूर्ण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित किया। विद्रोह के प्रतीक के रूप में आम की टहनियां और सूखी मिर्च को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। विद्रोह की तीव्रता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों को नागपुर से सेना बुलानी पड़ी, फिर भी वे वीर गुंडाधुर को पकड़ने में असफल रहे।

झांकी के पृष्ठ भाग में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए दर्शाया गया। उन्होंने अकाल के समय गरीबों और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई।

पूरी झांकी जनजातीय समाज के अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को सशक्त रूप में अभिव्यक्त करती रही और गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ की गौरवपूर्ण पहचान को राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया।

पुलिस विभाग को 8 नए साइबर थानों समेत आवासीय भवनों और नवीन थाना भवनों की मिली सौगात

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के 255 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का किया वर्चुअली लोकार्पण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नया रायपुर से वर्चुअली जुड़कर विभिन्न जिलों में 8 नए साइबर थानों और 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस आवासीय भवनों तथा थाना भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और पुलिस के जवानों को इस विशेष पहल के लिए शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन पुलिस विभाग के लिए अत्यंत सौभाग्य का है, क्योंकि 255 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने देखा कि साइबर थाना, एसडीओपी कार्यालय, चौकी भवन, ट्रांजिट हॉस्टल एवं आवासीय भवन अत्यंत सुंदर और सुविधाजनक बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए संबंधित एजेंसियों की सराहना करते हुए कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सकारात्मक वातावरण में कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और वे अपने कर्तव्यों का और अधिक प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकेंगे। श्री साय ने कहा कि सरकार का सतत प्रयास है कि कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर आवास एवं कार्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है और इससे सुदूर अंचलों तक भी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकेगा।

साइबर पुलिस थाना जिला-रायगढ़

साइबर पुलिस थाना जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा

साइबर पुलिस थाना जिला-जांजगीर-चांपा

साइबर पुलिस थाना जिला-जशपुर

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अनेक स्थानों पर साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की जा रही है। आज जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव जिलों सहित कुल 8 नए साइबर थानों का शुभारंभ किया गया है। इससे पूर्व प्रदेश के पांच जिलों में साइबर थाना संचालित हैं। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार अन्य जिलों में भी साइबर थाने स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही चार जिलों में भारत वाहिनी के कैंपस, नौ जिलों में नए थाना भवन, माना में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की चौकी तथा आवासीय भवनों का भी लोकार्पण किया गया। गृहमंत्री श्री शर्मा ने 255 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए इन निर्माण कार्यों एवं 8 नए साइबर थानों की स्वीकृति और लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, गृह विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, पुलिस महानिदेशक पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन श्री पवन देव, एडीजी श्री एसआरपी कल्लूरी, एडीजी श्री प्रदीप गुप्ता, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, एडीजी श्री दीपांशु काबरा, एडीजी श्री अमित कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही वनमंत्री श्री केदार कश्यप, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, विधायक श्री भईया लाल रजवाड़े, श्री ललित चंद्राकर, विधायक श्रीमती रायमुनि भगत एवं जनप्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी रहे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बालोद जिले के 21वीं भारत रक्षित वाहिनी करकाभाट, पुलिस थाना भवन सनौद, महासमुंद जिले के 20वीं भारत रक्षित वाहिनी परसदा, धमतरी जिले के पुलिस चौकी भवन करेलीबड़ी, रायपुर जिले के सेन्ट्रल आर्म्स स्टोर, 4थीं वाहिनी माना, ट्रांजिट हॉस्टल, बस्तर जिले के 19वीं भारत रक्षित वाहिनी करनपुर, बीजापुर जिले के पुलिस थाना भवन तर्रेम, पुलिस थाना भवन नैमेड़, सुकमा जिले के पुलिस थाना भवन चिंतागुफा, पुलिस थाना भवन चिंतलनार, कांकेर जिले के 22वीं भारत रक्षित वाहिनी भीरावाही, नारायणपुर जिले के पुलिस थाना भवन भरण्डा, पुलिस थाना भवन बैनुर, ट्रांजिस्ट हॉस्टल नारायणपुर, दुर्ग जिले के पुलिस थाना भवन पद्मनाभपुर, पुलिस थाना भवन पुलगांव, 36 अराजपत्रित एवं 48 प्रधान आरक्षक आवासगृह, एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन धमधा, बेमेतरा जिले के एस.डी.ओ.पी. कार्यालय भवन बेरला, राजनांदगांव जिले के एस.आई.बी. फिल्ड यूनिट, ट्रांजिट हॉस्टल, दुर्ग, सूरजपुर जिले के पुलिस चौकी कुदरगढ़, कोरिया जिले के 24 अराजपत्रित एवं 144 प्र.आर./आरक्षक आवासगृह बैकुण्ठपुर एवं ट्रांजिट हॉस्टल बलरामपुर का लोकार्पण किया।

जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां आज ढोल-मांदर की थाप बजती है

बस्तर पंडुम के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, हस्तशिल्प और आदिवासी रीति-रिवाजों को मिला मंच

बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और जनजातीय अस्मिता को सहजने एवं संवारने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज माँ दंतेश्वरी मंदिर के पावन प्रांगण में जिला स्तरीय बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बस्तर की लोकसंस्कृति, पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत एवं रीति-रिवाजों की जीवंत झलक देखने को मिली, जिसने उपस्थित जनसमूह को बस्तर की आत्मा से जोड़ दिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि आज बस्तर बदल रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है और देश-विदेश में बस्तर की एक नई पहचान बन रही है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां आज ढोल-मांदर की थाप बजती है।

बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना है-कश्यप

जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के शुभारंभ अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि बस्तर की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत को सहेजना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत दंतेवाड़ा जिले से हुई है और उनके जीवन का आधा से अधिक समय यहीं बीता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुसार बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। माँ दंतेश्वरी मंदिर, ढोलकाल, बारसूर, चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे अनेक प्रमुख पर्यटन स्थल बस्तर की पहचान हैं।

बस्तर पंडुम ने बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर पंडुम के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को विश्व पटल तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इस आयोजन में 12 विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बस्तर की संस्कृति को सहज और जीवंत रखा है, और यह हम सभी का कर्तव्य है कि इस सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखें। उन्होंने कहा कि पहले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में जहाँ कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, आज वहाँ ढोल-मांदर की थाप सुनाई दे रही है, जो बस्तर के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। उन्होंने आगे कहा कि हमें केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि पूर्वजों से मिली संस्कृति को उसकी पहचान बनानी है।

पहले अति संवेदनशील जिले आज आकांक्षी जिले में शामिल

श्री कश्यप ने कहा कि अब बस्तर से नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और यह क्षेत्र एक समृद्ध एवं विकसित बस्तर के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो जिले पहले अति संवेदनशील कहलाते थे, वे आज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों में शामिल हैं। उन्होंने युवा वर्ग से बस्तर के पारंपरिक गीत, संगीत जैसे ''आया माचो दंतेश्वरी'' और ''साय रेला'' जैसे पारंपरिक गीतों को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म में फॉलों कर प्रचार-प्रसार करने को आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला स्तरीय बस्तर पंडुम के स्टॉलों का निरीक्षण कर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लिया। कार्यक्रम को विधायक श्री चौतराम अटामी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नंदलाल मुड़ामी और कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने भी सम्बोधित किया।

कुआकोंडा पोटाकेबिन-2 के छात्रों के मलखंभ के प्रदर्शन ने लोगों का मन मोहा

सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रस्तुति के क्रम में कुआकोंडा पोटाकेबिन-2 के छात्रों ने मलखंभ विधा में साहसिक करतब करते हुए लोगों को तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी फुर्ती और कलाबाजियों से मंत्रमुग्ध करते हुए छात्रों ने मलखंभ का अद्भुत प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ग्राम मोखपाल के नतक दलों ने पारंपरिक नृत्य तथा ग्राम मड़से के कलाकारों ने ठेठ ग्रामीण हाट बाजार के जनजीवन की जीवन्त प्रस्तुति दी। इसके अलावा जगदलपुर से आए बादल एकेडमी से आए कलाकारों की प्रस्तुतियां भी सराहनीय रही।